सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 195, नई दिल्ली । मंगलवार, 24 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित भाव से समर्पित होना पड़ेगा।

03 मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ : देवेन्द्र यादव

06 अंधविश्वास की परतें

08 ढेंकनाल जिला चिकित्सा केंद्र देखने में बहुत सुंदर है, मरीज आने पर खाली रेफर कर रहे हैं

किसकी गलती : दिल्ली परिवहन विभाग या दिल्ली सरकार या इलेक्ट्रिक वाहन मालिक, बड़ा सवाल?

संजय बाटला

- क्या गलती करने वाले को मिलेगी सजा या मिलेगा ईनाम दुसरा बड़ा सवाल?
- दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की गलतियों की सजा भुगत रहे ई वाहन मालिक और कोई नहीं है सुनने वाला

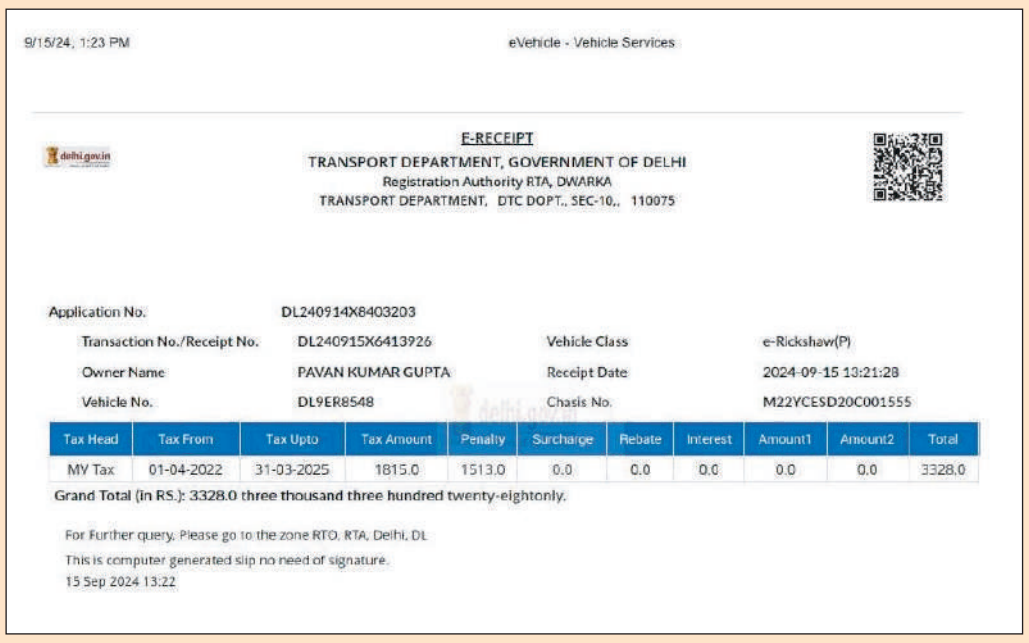

9/15/24, 1:23 PM eVehicle - Vehicle Services

E-RECEIPT
TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF DELHI
Registration Authority RTA, DWARKA
TRANSPORT DEPARTMENT, DTC DOPT., SEC-10,, 110075

Application No.	DL240914X8403203		
Transaction No./Receipt No.	DL240915X6413926	Vehicle Class	e-Rickshaw(P)
Owner Name	PAVAN KUMAR GUPTA	Receipt Date	2024-09-15 13:21:28
Vehicle No.	DL9ER8548	Chasis No.	M22YCESD20C001555

Tax Head	Tax From	Tax Upto	Tax Amount	Penalty	Surcharge	Rebate	Interest	Amount1	Amount2	Total
MV Tax	01-04-2022	31-03-2025	1815.0	1513.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3328.0

Grand Total (in RS.): 3328.0 three thousand three hundred twenty-eightonly.

For Further query, Please go to the zone RTO, RTA, Delhi, DL
This is computer generated slip no need of signature.
15 Sep 2024 13:22

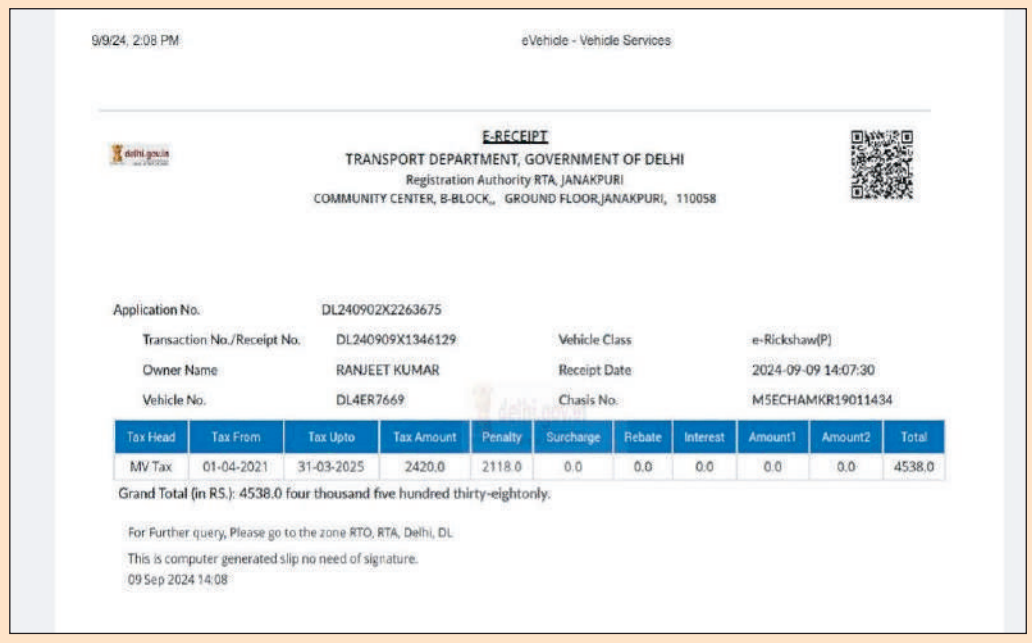

9/9/24, 2:08 PM eVehicle - Vehicle Services

E-RECEIPT
TRANSPORT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF DELHI
Registration Authority RTA, JANAKPURI
COMMUNITY CENTER, B-BLOCK,, GROUND FLOOR,JANAKPURI, 110058

Application No.	DL240902X2263675		
Transaction No./Receipt No.	DL240909X1346129	Vehicle Class	e-Rickshaw(P)
Owner Name	RANJEET KUMAR	Receipt Date	2024-09-09 14:07:30
Vehicle No.	DL4ER7669	Chasis No.	M5ECHAMKR19011434

Tax Head	Tax From	Tax Upto	Tax Amount	Penalty	Surcharge	Rebate	Interest	Amount1	Amount2	Total
MV Tax	01-04-2021	31-03-2025	2420.0	2118.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4538.0

Grand Total (in RS.): 4538.0 four thousand five hundred thirty-eightonly.

For Further query, Please go to the zone RTO, RTA, Delhi, DL
This is computer generated slip no need of signature.
09 Sep 2024 14:08

नई दिल्ली। दिल्ली में जितने भी व्यक्तियों ने व्यावसायिक गतिविधि के लिए ई वाहन खरीदे हैं पिछले 15 दिनों से अधिक से हो रहे हैं परेशान और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इधर से उधर पर परिवहन विभाग में कोई भी उन्हे सही और सपष्ट बताने को तैयार नहीं है की आखिर उन्होंने ई वाहन खरीद कर गलती क्या कर दी। **गलती करने और कराने वाले अधिकारी तो इस बाबत किसी वाहन मालिक से बात करने को भी तैयार नहीं** जी हां यह बहुत बड़ा सच है और सच को जानने की जब कोशिश करी गई तो सबने गोल गोल घुमाने की बाते की। **व्यावसायिक गतिविधि में शामिल वाहनों की प्रथम 8 साल तक वाहन मालिक को दो साल में वाहन जांच प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है और वाहन को परिवहन विभाग की अधिकृत शाखा पर ले जाना होता है जिसके लिए उनसे फीस जमा करवाई जाती है। *सभी प्रकार के व्यवसायिक श्रेणी में चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन मालिक जब फिटनेस की फीस कटवाने आनलाइन आवेदन करने पहुंचे तो उनसे उनके पंजीकरण की तारीख से अब तक का रोड टैक्स जुर्माने सहित जमा करवाने की मांग हो रही है और यह वह रोड टैक्स है जो दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को दिल्ली सरकार ने माफ कर रखा था। *आपकी जानकारी हेतु बता दें की कुछ दिनों पहले बिना किसी सूचना के दिल्ली परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन पर दिल्ली सरकार द्वारा घोषित सभी छुट (पंजीकरण फीस और रोड टैक्स) पंजीकरण के समय वसूलना यानी लेना शुरु कर दिया था** इस बाबत जब विभाग से जानकारी/ आदेश/ निर्देश की कापी मांगी गई तो **उपायुक्त इलैक्ट्रिक शाखा का जवाब था की इसके लिए आदेश / निर्देश जारी करने की जरूरत क्या है क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही छूट की समय सीमा समाप्त हो गई है और नया कोई आदेश जारी नही हुआ है।** और उसी दिन से नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों से अन्य फ्यूल श्रेणी वाले वाहनों की तरह सभी प्रकार की फीस लेना शुरु कर दिया और साथ ही शुरू करवा दिया उस तारीख से पहले खरीदे गए वाहनों के लिए आफत का आदेश यानी उनके पंजीकरण की तारीख से अब तक रोड टैक्स वह भी जुर्माने के साथ मागने का। **अब बताए की इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों की इसमें क्या गलती है जो दिल्ली परिवहन विभाग दिल्ली सरकार का नाम लेकर ई रिक्शा मालिक, ऑटो मालिक, टैक्सी मालिक आदी सभी को चुना लगाने यानी गैर सवेधानिक फीस वह भी जुर्माने के साथ भरने के लिए मजबूर कर रहा है। *इन सभी कार्यों को दिल्ली सरकार का नाम लेकर करवाने वाला कोन है यह तो सिर्फ विशेष आयुक्त इलेक्ट्रिक शाखा या उपायुक्त इलेक्ट्रिक शाखा ही बता सकते है पर दोनों के सिर पर आकाओं का हाथ है** इसलिए यह जानना की यह गलती जानबूझकर परिवहन विभाग द्वारा की गई है या दिल्ली सरकार के आदेश पर परिवहन विभाग ने की है थोड़ा मुश्किल है पर इस का समाधान तभी सम्भव है जब उपराज्यपाल या दिल्ली सरकार या प्रशासनिक अधिकारी परिवहन आयुक्त लिखित आदेश इसे सभी के लिए माफ करने के आदेश जारी करे। **गलती करे परिवहन विभाग के अधिकारी और परेशान हो जनता** यह सब लगातार पिछले चार सालों से देखने को मिल रहा है पर इन से जवाब सवाल करने वाले भी है चुप आखिर क्यों? यह तो वही जानते हैं क्योंकि वह वो हैं जिनसे सवाल जवाब करना तो दूर जनता को मिलने में भी मुश्किलें है।

Post

Sanjay Bathla
@bathlasa

कोन जिम्मेदा, गलती करने वाले को मिलेगीसजा या ईनाम, बड़ा सवाल? दिल्ली के व्यवसायिक इलेक्ट्रिक वाहन मालिक परेशान , क्या देगें आप जवाब
@AmitShah @nitin_gadkari @LtGovDelhi @CMODelhi @ashishkundra @kgahlot @newsparivahan @PTI_News @ANI @News18India @ZeeNews
Translate post

facebook.com
Sanjay Bathla
"दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग की गलतियों की सजा भुगत रहे ई वाहन मालिक और कोई नहीं हे सुनने वाला" दिल्ली में जितने भी व्यक्तियों...

10:24 pm · 23 Sep 2024 · 4 Views

लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर चलती ट्रेन के आगे कूदा शख्स, हुई मौत; रेल सेवाएं रहीं बाधित

दिल्ली मेट्रो में एक यात्री के ट्रेन के आगे कूद जाने से सेवाएं बाधित हो गईं। घायल यात्री को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। कुछ समय के लिए विश्वविद्यालय-कुतुब मीनार के बीच ट्रेन सेवाओं को रोकना पड़ा जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। शाम 6.15 बजे सामान्य ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गईं।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल पर ट्रेन सेवाएं उस समय बाधित हो गईं, जब लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री मेट्रो ट्रेन के आगे कूद गया। घायलावस्था में उसे आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान राजस्थान के अलवर निवासी देवेंद्र कुमार (28 वर्ष) के तौर पर की गई है।

डीएमआरसी के अधिकारी के मुताबिक, शाम 5.47 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन (समयपुर बादली की ओर जाने वाली) ट्रेन के आगे एक व्यक्ति ने छलांग लगा दी। गनीमत रही उस समय मेट्रो रेल की रफ्तार बहुत धीमी थी। यात्री को मेट्रो में तैनात जवानों मदद से निकाला गया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने शख्स को मृत घोषित कर दिया।

कुछ समय के लिए यातायात रही बाधित

इस दौरान विश्वविद्यालय-कुतुब मीनार के बीच ट्रेन सेवाओं को कुछ समय के लिए रोका गया, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। हालांकि शाम 6.15 बजे सामान्य ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गईं।

दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के कॉरिडोर पर दौड़ेगी बिना ड्राइवर की ट्रेन

सुषमा रानी

दिल्ली मेट्रो फेज 4 के निर्माणाधीन तीनों कॉरिडोर के लिए आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में बन रही नई मेट्रो ट्रेनों में से पहली ट्रेन डीएमआरसी को सौंप दी गई। यह ट्रेन पूरी तरह से चालक रहित होगी। फेज चार में करीब 65 किलोमीटर नेटवर्क के तीन मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है जिसमें जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मौजपुर-मजलिस पार्क और तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर शामिल हैं।

नई दिल्ली। फेज चार के निर्माणाधीन तीन कॉरिडोर के लिए आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में बनाई जा रही नई मेट्रो ट्रेनों में से पहली ट्रेन सोमवार को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को सौंप दी गई। जिसे सड़क मार्ग के जरिये कंटेनर ट्रक से दिल्ली रवाना कर दिया गया। फेज चार की नई ट्रेनें पूरी तरह चालक रहित स्वचालित होंगी।

फेज चार में करीब 65 किलोमीटर नेटवर्क के तीन मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। जिसमें जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम, मौजपुर-मजलिस पार्क व तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर शामिल है। जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर वर्तमान मजेंटा लाइन व मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर पिंक लाइन की विस्तार परियोजना है। तुगलकाबाद-एरोसिटी कॉरिडोर की पहचान गोल्डन लाइन के रूप में होगी।

52 ट्रेनों का दिया था कॉन्ट्रेक्ट

इन तीनों कॉरिडोर के लिए डीएमआरसी ने नवंबर 2022 में छह कोच की 52 मेट्रो ट्रेनें (312 कोच) खरीदने का कॉन्ट्रेक्ट दिया था। मेक इन इंडिया के तहत इस वर्ष फरवरी में श्री सिटी में इन ट्रेनों का निर्माण शुरू हुआ था। इन ट्रेनों की अधिकतम गति 95 किमी प्रति घंटे होगी और 85 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से परिचालन हो सकेगा।

अक्टूबर में पहुंच जाएगी पहली ट्रेन

पहली ट्रेन की चाबी मिलने के बाद डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने फेज चार की मेट्रो परियोजनाओं के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में पहली ट्रेन के सभी छह कोच दिल्ली में पिंक लाइन के डिपो में पहुंच जाएंगे, जहां सभी छह कोच को जोड़कर ट्रेन तैयार कर ट्रायल किया जाएगा। बाकी नई ट्रेनें चरणबद्ध तरीके से दिल्ली पहुंचेंगी। 13 ट्रेनें गोल्डन लाइन पर, 24 ट्रेनें मजेंटा लाइन पर 15 ट्रेनें पिंक लाइन पर इस्तेमाल होंगी।

नोएडा एयरपोर्ट से दुबई-सिंगापुर के लिए शुरू होगी फ्लाइट, 1 अक्टूबर को लिए जाएंगे बड़े फैसले

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही यात्री सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। शुरुआत में सिंगापुर और दुबई के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा सकती हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। एयरपोर्ट के संचालन के लिए केंद्रीय विभागों की अनापत्ति ट्रायल आदि होने हैं। इनकी समय सारिणी तय करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय ने नियाल को सौंपी है।

ग्रेटर नोएडा। सिंगापुर और दुबई की अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) की शुरुआत हो सकती है। देश के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने पर फैसला होगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्री सेवा का संचालन शुरू करने के लिए समय सारिणी तय करने के निर्देश नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (NIAL) को दिए हैं। कंपनी ने एक अक्टूबर को इसके लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, महानिदेशक नागरिक विमानन, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. में प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अगले वर्ष अप्रेल में शुरू होगी विमान सेवा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री सेवाओं का संचालन अप्रैल 2025 से शुरू होगा। इससे पहले एयरपोर्ट के संचालन के लिए केंद्रीय विभागों की अनापत्ति, ट्रायल आदि होने हैं। इनकी समय सारिणी तय करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय ने नियाल को सौंपी है।

बैठक में क्या होगा तय

एक अक्टूबर को होने वाली बैठक में यह भी तय हो जाएगा कि पहले दिन एयरपोर्ट से कितनी फ्लाइट होंगी। इनका संचालन देश के किन शहरों के लिए होगा। इसके साथ ही पहले ही दिन नोएडा एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू होने की भी संभावना है। सिंगापुर व दुबई के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरूआत हो सकती है।

बैठक में शामिल होने वाले एएआई, डीजीसीए, विकासकर्ता कंपनी वाईआईएपीएल के अधिकारी यात्री सेवाओं की शुरूआत के लिए जरूरी एयरो ड्रोम लाइसेंस (Aerodrome License) के लिए आवेदन व लाइसेंस जारी करने के लिए समय अवधि पर भी चर्चा करेंगे।

और किस पर होगी चर्चा

इसके अतिरिक्त केलिब्रेशन सर्टिफिकेट, फ्लाइट प्रोसेजर का निर्धारण एवं डीजीसीए को सौंपने, ट्रायल के लिए डीजीसीए की स्वीकृति, फ्लाइट ट्रायल के लिए डीजीसीए की अनुमति, कार्मशियल फ्लाइट का ट्रायल, एयरपोर्ट पर लगाए गए उपकरणों का प्रमाणीकरण, एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे।

साथ ही यात्री सेवाओं की शुरुआत की जानकारी जारी करने आदि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय सारिणी विभागों के प्रतिनिधियों की सहमति से तय की जाएगी। नियाल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि एक अक्टूबर को होने वाली बैठक में एयरपोर्ट के संचालन से संबंधित कई अहम फैसले लिए जाएंगे।

शुरुआत में 65 फ्लाइट के संचालन की संभावना

एयरपोर्ट की शुरुआत में एक दिन में 65 फ्लाइट की संभावना है। हालांकि एक अक्टूबर को होने वाली बैठक में इनकी संख्या अंतिम रूप से निर्धारित की जाएगी। 1334 हे. में बन रहे एयरपोर्ट की शुरुआत में एक रनवे से यात्री सेवाओं की शुरुआत होगी।

रनवे, एटीसी का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दस सितंबर को एयरपोर्ट की निर्माण प्रगति का जायजा लिया था।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

महालक्ष्मी व्रत से जीवन में नहीं आता है आर्थिक संकट

प्रज्ञा पाण्डेय

महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के पांच दिन बाद रखा जाता है. पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से होती है और समापन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है. इस तरह पूरे 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत रखा जाता है।

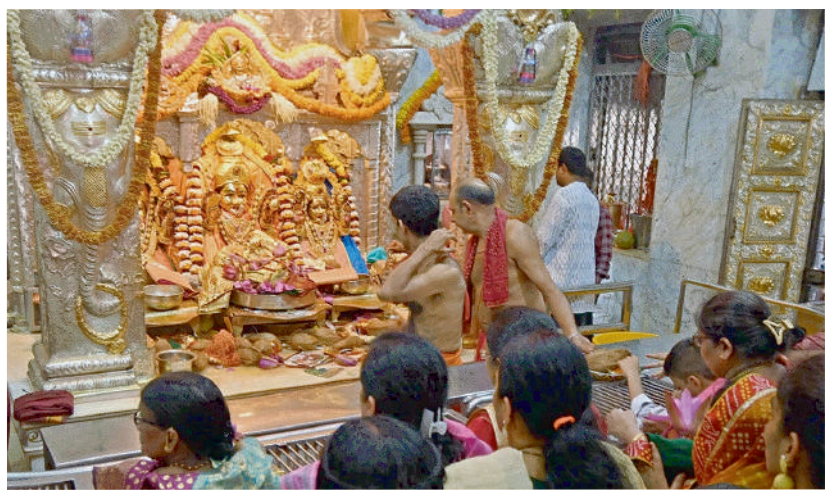

24 सितम्बर को महालक्ष्मी व्रत है, हिन्दू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। महालक्ष्मी व्रत से न केवल मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है बल्कि श्री विष्णु भी भक्तों को आर्शीवाद देते हैं, तो आइए हम आपको महालक्ष्मी व्रत का महत्व एवं पूजा विधि के बारे में बताते हैं।

जानें महालक्ष्मी व्रत के बारे में

महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के पांच दिन बाद रखा जाता है. पंचांग के अनुसार इसकी शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि से होती है और समापन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है. इस तरह पूरे 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत रखा जाता है। इस साल 11 सितंबर 2024 से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होगी और 24 सितंबर 2024 को इसका समापन होगा।11 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत आयुष्मान और प्रीति योग के साथ होगी। महालक्ष्मी व्रत पूजा को गजलक्ष्मी और हाथी पूजा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हाथी की पूजा की जाती है।

कब है महालक्ष्मी व्रत

ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस साल महालक्ष्मी व्रत 24 और 25 सितंबर दोनों दिन हैं। आपको बता दें महालक्ष्मी व्रत शायं कालीन और रात्रिकालीन व्रत होता है, चूंकि सप्तमी तिथि 24 सितंबर की शाम को 5:45 पर आ जाएगी।

महालक्ष्मी व्रत का शुभ मुहूर्त

सप्तमी तिथि

सप्तमी तिथि का प्रारंभः 24 सितंबर को शाम 05:45 बजे से

सप्तमी तिथि की समाप्तिः 25 सितंबर को शाम 04:44 मिनट तक

क्यों रखा जाता है महालक्ष्मी का व्रत

जीवन में सभी तक की सुख समृद्धि और धन संपत्ति प्राप्ति के लिए दीपावली पर मां लक्ष्मी की तरह क्वांर के महीने में महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इसे गज लक्ष्मी व्रत कभी कहते हैं।

महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी कथा

एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह नियमित भगवान विष्णु (Lord Vishnu) की पूजा करती थी। भक्त की श्रद्धा-भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णुजी ने उसे दर्शन दिए और भक्त से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणी ने कहा कि, मैं बहुत गरीब हूं मेरी इच्छा है कि मेरे घर पर मां लक्ष्मी का वास रहे। विष्णुजी ने ब्राह्मणी को एक उपाय बताया, जिससे कि उसके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो। भगवान विष्णु ने बताया कि, तुम्हारे घर से कुछ दूर एक मंदिर है वहां एक स्त्री आकर उपले थापती है। तुम उस स्त्री को अपने घर पर आमंत्रित करो, क्योंकि वही मां लक्ष्मी है। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उस स्त्री को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और उस स्त्री ने ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिनों तक मां लक्ष्मी की पूजा करें।

ब्राह्मणी ने 16 दिनों तक मां लक्ष्मी की उपासना की, इसके बाद मां लक्ष्मी ने गरीब ब्राह्मणी के घर निवास किया। इसके बाद उसका घर धन-धान्य से भर गया। मान्यता है कि, तभी से 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हुई। जो व्यक्ति 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत रखकर लक्ष्मी जी की उपासना करता है मां लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

महालक्ष्मी व्रत का हिन्दू धर्म में है खास महत्व

महालक्ष्मी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वैसे तो यह खासतौर महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही देश के अन्य क्षेत्रों में भी लोग इस व्रत को करते हैं। इसमें मां लक्ष्मी के विभिन्न रूपों में पूजा होती है। पंडितों के अनुसार महालक्ष्मी व्रत रखने और पूजन करने वालों पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उसे जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है।

महालक्ष्मी व्रत में ऐसे करें पूजा

इस साल महालक्ष्मी व्रत कई शुभ योग के साथ शुरू हो रहा है। ऐसे में देवी मां की पूजा करने के लिए पहले सुबह ही स्नान कर लें। इसके बाद पूजा स्थान पर नारियल, कलश, कपूर और घी आदि सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। अब सबसे पहले पूजा स्थल पर एक चौकी लगाएं। इस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए। फिर चौकी पर माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित कर दें। इसके बाद उन्हें चुनरी चढ़ाएं। अब 16 श्रृंगार के सामानों के साथ नारियल, चंदन, पुष्प, अक्षत, फल समेत सभी चीजें अर्पित करते जाए। फिर आप एक कलश में साफ जल भरकर उसपर नारियल रखे। बाद में इसे माता के पास स्थापित कर दें। लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप करते हुए उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर सभी फल मिठाई उन्हें अर्पित कर दें। अब महालक्ष्मी आरती करें।

इसके बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। महालक्ष्मी व्रत पूरे 16 दिनों तक रखा जाता है, हालांकि यह निर्जला व्रत नहीं होता, लेकिन अन्न ग्रहण करने की मनाही होती है। आप इस व्रत को फलाहार रख सकते हैं, 16वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि आप 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करने में असमर्थ हैं तो शुरुआत के 3 या आखिर के 3 व्रत रख सकते हैं। अंत में पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। पूजा में जाने-अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। अंत में परिवार के सदस्यों के साथ पूजा-स्थल पर मौजूद सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें।

महालक्ष्मी व्रत का महत्व

इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। इसे करने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। महालक्ष्मी व्रत की कथा अनुसार इस व्रत को माता कुंती ने किया था। इसके लिए स्वर्गलोक से गजराज धरती पर आए थे।

रवि योग में महालक्ष्मी व्रत 2024

महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ रवि योग में हो रहा है। रवि योग आज रात 9 बजकर 22 मिनट से कल सुबह 6 बजकर 5 मिनट तक है। महालक्ष्मी व्रत के पहले दिन प्रीति योग सुबह से लेकर रात 11:55 बजे तक है, उसके आयुष्मान होगा।

मुश्किल ब्रेकअप के बाद फिर से डेटिंग की दुनिया में वापसी कैसे करें?

एकता

आप इससे आगे बढ़ सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ फिर से डेटिंग शुरू कर सकते हैं। यह जल्दबाजी या खुद पर दबाव डालने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बार में एक कदम उठाने के बारे में है। कुछ मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सलाह के साथ, आप इस चरण से गुजर सकते हैं और सीख सकते हैं।

लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते से अलग होना मुश्किल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल क्या है? डेटिंग की दुनिया में वापस लौटना। यह अजीब, अपरिचित और बिल्कुल डरावना लग सकता है। एक पल में, आप अपने नए साथी की बाहों में लिपटे हुए होते हैं, और अगले ही पल, आप अपने पिछले रिश्ते की यादों में खो जाते हैं। आप अपना सिर उनके कंधे पर टिकाना चाहते हैं, लेकिन फिर, अचानक, एक बुरे लगाव की दर्दनाक याद सामने आ जाती है।

हम जानते हैं कि यह डरावना है और हम यह भी जानते हैं कि लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते के टूटने से आगे बढ़ना मुश्किल है। ब्रेकअप के बाद आगे बढ़ना ऐसा महसूस करा सकता है जैसे आप अपने साथ आत्म-संदेह, चिंता और यहाँ तक कि अवसाद का बोझ भी ढो रहे हैं। खुद से सवाल करना और यह सोचना कि क्या आप कभी फिर से 'सामान्य' महसूस कर पाएंगे, सामान्य है।

लेकिन बात यह है कि उम्मीद है। आप इससे आगे बढ़ सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ फिर से डेटिंग शुरू कर सकते हैं। यह जल्दबाजी या खुद पर दबाव डालने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बार में एक कदम उठाने के बारे में है। कुछ मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सलाह के साथ, आप इस चरण से गुजर सकते हैं और सीख सकते हैं कि अतीत के बोझ के बिना, स्वस्थ, सार्थक तरीके से डेटिंग कैसे करें।

कपल्स थेरेपिस्ट पैट्रिस ले गोय ने कहा कि आप डेटिंग के तरीके के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं या किसी नए व्यक्ति के साथ अंतरंग होने का डर हो सकता है। यह अजीब भी लग सकता है, या ऐसा लग सकता है कि आप 'धोखा' दे रहे हैं, जब आप किसी लंबे समय के साथी के साथ रहने के बाद किसी नए व्यक्ति के साथ कुछ साझा करते हैं या करते हैं।

सुनिश्चित करें कि आप तैयार हैं- किसी नए रिश्ते में आने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप डेट करने के लिए तैयार हैं। ब्रेकअप के बाद आप अकेला महसूस कर सकते हैं और इस अकेलेपन को भरने के लिए अक्सर लोग गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। इसलिए किसी रिश्ते में आने में जल्दबाजी करने की कोशिश करने की जल्दी न करें नहीं तो खुद को ही चोट पहुंचा बैठेंगे। डॉ. ले गोय कहते हैं, 'कुछ संकेतों में अपने पिछले रिश्ते पर लगातार चर्चा करने और उसका विश्लेषण करने की ज़रूरत महसूस न करना शामिल है। यह दर्शाता है कि आप किसी स्थायी नाराज़गी या पछतावे को नहीं पाल रहे हैं जो नए रिश्ते में भी बना रह सकता है।'

डेटिंग से सीखने की कोशिश करें- डेटिंग का मतलब अपने एक्स के द्वारा छोड़े गए खालीपन को भरना या सेक्स करना नहीं है, यह इन चीजों से कहीं ज़्यादा है। जब आप डेट करने के लिए तैयार हों तो सुनिश्चित करें कि आप जीवन और प्यार के नए दृष्टिकोण सीखने के लिए अपना दिमाग खोलें। एक्सपर्ट कहते हैं कि खुद को डेटिंग के लिए खोलना आपको इस सोच में डाल सकता है, 'मैं कुछ अच्छे लोगों से मिलने जा रही हूँ। उनमें से कुछ मेरे दोस्तों को बाद में बताने के लिए एक मज़ेदार कहानी होगी, और शायद कोई मेरा अगला प्रेमी बन जाए, और मुझे उन दोनों से कोई परेशानी नहीं है।

डेटिंग से पहले अकेले वो करें जो आपको पसंद है- डेट पर जाने से पहले ऐसी गतिविधियों से शुरुआत करें जो आपको अकेले में पसंद हों। फैंसी रेस्टोरेंट या भीड़-भाड़ वाले बार हमेशा पहली डेट के लिए आदर्श नहीं होते, खासकर तब जब आप पहले से ही नर्वस महसूस कर रहे हों। एक्सपर्ट ने कहा, 'पहली डेट पर जाना बहुत ज़्यादा खर्चीला या आपके कम्फर्ट जोन से बाहर होना ज़रूरी नहीं है।' ऐसी जगहों पर जाएं जहां आप सहज महसूस करें। अगर आपको खाने-पीने का शौक है, तो अपनी पसंदीदा स्थानीय जगह पर जाएं। अगर आपको किताबों की दुकानें पसंद हैं, तो किसी आरामदायक कैफे में चाय पिएं और अलमारियों को ब्राउज़ करते हुए बातचीत करें। परिचित वातावरण चुनने से अनुभव कम डरावना लग सकता है और आपको आराम करने में मदद मिल सकती है।

ईमानदार होना आपकी कमजोरी नहीं है- याद रखें, ईमानदार होना ठीक है। अगर आप नर्वस महसूस कर रहे हैं तो आपको ऐसा व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी तरह से सहज हैं। डॉ. ले गोय कहते हैं, 'डेट को यह बताना बिल्कुल ठीक है कि आप इस मामले में नए हैं और पूरी तरह से सहज नहीं हैं।' खुलकर बात करने से आप दोनों के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। वे आपकी ईमानदारी की सराहना कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप चुप या चिंतित क्यों हैं। साथ ही, वास्तविक होना आपको आराम करने में मदद करता है, और अगर आप खुद नहीं हो सकते, तो इसका क्या मतलब है?

अगर आप भी नेचर लवर हैं, तो इन वाइल्डलाइफ सैन्चुरी को जरुर देखने जाएं, प्राकृतिक खूबसूरती देखकर दंग रह जाएंगे

कई लोगों को प्राकृतिक नजारे देखने के काफी शौकीन होते हैं। अगर आप भी नेचर लवर हैं तो आप यहां मौजूद कुछ वाइल्डलाइफ सैन्चुरी को जरुर एक्सप्लोर करना चाहिए। आइए हम आपको इस लेख में बताते हैं कि आप कहां-कहां वाइल्डलाइफ सैन्चुरी देखने के लिए जा सकते हैं।

वैसे प्रकृति के साथ समय बिताने से मानसिक रुप से काफी शांति मिलती है। ऐसे कई लोग है जो नेचर लवर हैं और उन्हें वन्यजीवों को करीब से देखना भी काफी पसंद होता है। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और भारत की सुंदर वाइल्डलाइफ सैन्चुरी देखना चाहते हैं, तो आप किसी भी नेचर लवर के घूमने के लिए एकदम सही है। इन खूबसूरत वाइल्डलाइफ सैन्चुरी में आप प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे को देख सकते हैं या जीवंत पक्षी प्रजातियों को देखना चाहते हों, या फिर प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद लेना चाहते हों, तो असम में आपको सब मिल जाएगा।

काजीरंगा नेशनल पार्क

जब कहीं वाइल्डलाइफ सैन्चुरी घूमने की बात आती हैं तो असम का काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सबसे पहले आता है। दरअसल, गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित यह नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत के सबसे प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ सैन्चुरीज में से एक है। यहां पर आप एक सींग वाला गैंडे के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि, काजीरंगा नेशनल पार्क 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और गैंडों के अलावा, यहां हाथियों, बाघों, जंगली भैंसों और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएगी। गौरतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी पार्क से होकर बहती है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है।

मानस नेशनल पार्क

अगर आप असम जा रहे हैं तो आपको मानस नेशनल पार्क जरुर जाना चाहिए। दरअसल, यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बक्सा, चिरांग और कोकराझार जिले में स्थित है। इसको सबसे बेहतरीन वाइल्डलाइफ सैन्चुरी में से एक माना जाता है। यहां पर घना जंगल और घास के मैदानों का मिश्रण है। यहां आपको बंगाल टाइगर, पिग्मी हॉग, भारतीय हाथी और असम रूफ्ड कछुए सहित अपनी लुप्तप्राय प्रजातियां देखने को मिल जाएगी।

गरमपानी वाइल्डलाइफ सैन्चुरी

असम के कार्बी आंगलोंग जिला में स्थित है गरमपानी वाइल्डलाइफ सैन्चुरी। आपको बता दें कि, यह असम के सबसे पुराने वाइल्डलाइफ सैन्चुरी में से एक है, जो लगभग 6.05 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहां पर आपको प्राकृतिक गर्म झरनों और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। गरमपानी वाइल्डलाइफ सैन्चुरी में हाथियों, तेंदुओं और कई पक्षी प्रजातियों सहित कई तरह के वन्यजीव आपको देखने को मिल जाएंगे।

दिवाली की सफाई में इस तरह से रखें 2BHK फ्लैट में सामान, फिर भी बच जाएगी जगह

जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनकों जगह को लेकर हमेशा परेशानी ही रहती है। 2BHK फ्लैट में रहने के लिए अगर बड़ी फैमिली है तो जगह की कमी हमेशा बनीं रहती है। लेकिन सही तरह से से सामान रखने से आप 2 बीएचके फ्लैट को मैक्सिमाइज कर सकती हैं। आइए आपको टिप्स बताते हैं दिवाली की सफाई के समय किस तरह से रखें सामान।

बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले लोल ज्यादातर 2BHK फ्लैट में रहना पसंद करते हैं। फ्लैट में हमेशा स्पेस कम ही नजर आती है। कपल लोगों के लिए 2BHK फ्लैट का स्पेस काफी माना जाता है लेकिन बड़ी फैमिली बढ़ने की स्थिति में घर का स्पेस कम लगने लगता है। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है कि घर के स्पेस को ही मैक्सिमाइज करना सही होता है। दिवाली के सफाई के दौरान सामान को सही तरीके से आप फिट करके स्पेस बढ़ा सकते हैं।

मल्टीपर्पस फर्नीचर

जब आपको फर्नीचर की जरुरत होती है, तो यह काफी स्पेस ले लेता है। ऐसे में 2 बीएचके फ्लैट में स्पेस में काफी समस्या आती है। इससे अच्छा है कि मल्टीपर्पस या स्पेससेविंग फर्नीचर खरीदें। आप सोफा कम बेड खरीद सकते है। फोल्डेबल बेड को आप दिन में स्टोर कर सकती हैं। आप एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल भी खरीद सकते हैं, जो आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं।

वर्टिकल स्पेस का यूज

आप वर्टिकल स्टोरेज सॉल्यूशन पर भी फोकस कर सकती हैं। इस तरह से आप सामान आसानी से रख सकते हैं। आपको वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल-माउंटेन शेल्फ से लेकर कैबिनेट और हैंगिंग आर्गेनाइजर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। इन पर आप बुक्स या डेकोरेटिव आइटम्स को रखने में मदद रख सकते हैं।

कॉर्नर का प्रयोग करें

फ्लैट के अलग-अगल कोनों के स्टोरेज और होम डेकोर के लिए यूज कर सकते हैं। कॉर्नर के लिए मल्टीपर्पस अलमारी या वॉल माउंटेन शेल्फ बनवा लीजिए। जहां बहुत सा सामान रखने की जगह मिल सकता है। लिविंग एरिया के लिए एल शेप के सोफे या डेस्क बनवाएं, ऐसा करने से लिविंग एरिया का सेंट्रल स्पेस बच जाएगा।

स्वस्थ दिल से लेकर वजन कंट्रोल करने के लिए अंडा सबसे फायदेमंद, किस तरह से करें सेवन

अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन मौजूद होता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। रोजाना दो अंडे खाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। अंडे खाने से दिल भी हेल्दी रहता है। क्या आप जानते हैं अंडे खाने से वजन भी कंट्रोल में रहता है आइए जानते हैं किस तरह से इसका सेवन करें।

अक्सर आपने सुना होगा संडे हो या मंडे रोज खाओं अंडे। क्योंकि अंडा खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। वैसे अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन मौजूद होता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। रोजाना दो अंडे खाने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। अंडा खाने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आंखों और दिल के लिए भी अच्छा माना जाता है। अंडे में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हार्ट को बेहतर बनाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, अंडे में ल्यूटिन और जेक्सैंथिन होते हैं, जो मोतियाबंद के खतरे को कम करता है।

अंडे में होता है भरपूर प्रोटीन

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन की जरुरत काफी होती है। वयस्कों को अपने वजन के हर किलोग्राम के लिए रोजाना आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन की जरुरत होती है। अंडे में पर्याप्त प्रोटीन होता है। फलियों और मीट को भी आप अपने डाइट में शमिल कर सकते हैं।

विटामिन ए से भूरपूर अंड

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए काफी जरुरी है। यह हमारे आई हेल्थ, मेटाबॉलिज्म और सेल्स डेवलपमेंट के लिए जरुरी है। इसके अलावा यह हमारे इम्यून फंक्शन और स्किन के लिए भी आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना लगभग 3000 IU विटामिन ए की जरुरत होती है। यदि आप रोजाना दो उबले अंडे का सेवन करते हैं तो आपको विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलेगा।

विटामिन डी मिलता है

रोजाना आप 2 उबले अंडा खाते हैं तो आपको 82 IU विटामिन डी प्राप्त होगा। हड्डियों के लिए विटामिन डी सबसे जरुरी माना जाता है। इसके साथ ही यह इम्यून सिस्टम के लिए सबसे बेहतरीन होता है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिले तो हड्डियों से जुड़े रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।

विटामिन बी2 और विटामिन बी12 मिलता

आंखों और स्किन के लिए विटामिन बी2 की जरुरी माना जाता है। प्रतिदिन अंडा खाने से विटामिन बी2 प्राप्त होता है। वहीं, विटामिन बी12 से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है जो शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसलिए रोजाना 2 माइक्रोग्राम विटामिन बी12 की जरुरत होती है। वहीं, एक व्यक्ति को प्रतिदिन 1.3 मिलीग्राम विटामिन बी2 होना चाहिए।

अंडे में फोलेट, आयरन और जिंक होता है

अंडा में आयरन, जिंक और फोलेट भी पाया जाता है। कम से कम रोजाना 400 माइक्रोग्राम फोलेट की जरुरत होती है। आप अंडे के साथ ही प्रोटीन रिच और भी चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। अंडे में 1.2 मिलीग्राम आयरन होता है। आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के उत्पादन करता है। वहीं, इसके साथ ही अंडे में जिंक 1.1 मिलीग्राम पाया जाता है। दरअसल, जिंक इम्यून फंक्शन को भी ठीक करता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पदभार संभाला

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। सीएम आतिशी अरविंद केजरीवाल के सम्मान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को खाली छोड़कर एक अन्य कुर्सी पर बैठ कर सरकार चलाएंगी। सीएम आतिशी ने कहा कि चार महीने बाद दिल्ली के लोग अपने प्यार और भरोसे के साथ दोबारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब तक उनकी यह कुर्सी उनका इंतज़ार करेगी।

दिल्ली सचिवालय में पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि जिस तरह भरत जी ने 14 सालों तक भगवान श्रीराम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह अगले 4 महीने तक मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी।

सीएम आतिशी ने कहा कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। आज मेरे मन की वही व्यथा है, जो भरत की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्षों के लिए अयोध्या से वनवास के लिए गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा था।

सीएम आतिशी ने कहा कि भगवान श्रीराम अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल तक वनवास में रहे। इसलिए भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी जिंदगी हम सभी के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की मिसाल रखी है। पिछले 2 साल से भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा ने उनपर झूठे मुकदमे लगाए, गिरफ्तार किया और 6 महीने तक जेल में रखा।

उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानता दी, तब कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण थी। आतिशी ने कहा कि कोई और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं तबतक इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जबतक दिल्ली के लोग मेरी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते और उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया।

सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि 4 महीने बाद फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली के लोग अपने प्यार और भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तबतक यह कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और अरविंद केजरीवाल का इंतज़ार करेगी।

सीएम आतिशी ने ट्वीट कर कहा कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन में वही व्यथा है जो भरत के मन में थी। जब भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम 14 साल के वनवास पर गए थे और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा था। जैसे भरत ने 14 साल भगवान श्री राम की खड़ाऊं रख कर अयोध्या का शासन सम्भाला, वैसे ही मैं 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी।

मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ : देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में 6 महीने जेल में रहकर आए एक व्यक्ति की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से तुलना करने पर मुझे भारी आपत्ति है। आतिशी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में एक कुर्सी खाली छोड़कर यह कहना कि जिस प्रकार 14 साल के बनवास के बाद भगवान राम ने अयोध्या का शासन संभाला, 4 महीने बाद अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली की जनता को सिर्फ 4 महीने ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को झेलना है क्योंकि रोज-रोज की नौटंकी से दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है।

यादव ने कहा कि जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुँचकर मुख्यमंत्री आतिशी ने भ्रष्टाचारी पूर्व मुख्यमंत्रीअरविन्द केजरीवाल के नाम पर सभी मर्यादाओं धज्जियां उड़ाते हुए सभी हद पार कर दी है। आतिशी से दिल्ली की जनता को जो कुछ उम्मीदें थी, वो उनके इस अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कदम से पूरी तरह धूमिल हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल को मिली जमानत पर आतिशी द्वारा कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को दुर्भावना को बताया, कहकर सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतिशी ने अपने आप को डमी मुख्यमंत्री पेश किया है उसके बाद सरकार से कोई उम्मीद बची नही है, जिसकी दिल्ली की जनता आस लगाए बैठी थी कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने उनकी कुछ समस्याओं का समाधान निकलेगा। आज कि आतिशी की हरकत के बाद लोगों को आम आदमी पार्टी से, उसके नेताओं से, मंत्रियों अथवा मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले केजरीवाल और अब आतिशी दिल्ली की जनता की धार्मिक भावनाओं भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके औछी राजनीति कर रही है। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके औछी राजनीति करने में आप पार्टी और भाजपा एक दूसरे के पूरक है।

यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी ने अपनी कुर्सी के बराबर में एक और खाली कुर्सी छोड़कर क्या साबित करना चाहती है? अगर मर्यादा और राम राज्य की बात कर रही हैं तो केजरीवाल के 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाऐं। CAG की 11 विभागों की रिपोर्ट में दबे भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करें और भ्रष्टाचार में आरोपी नेताओं पर आरोप सिद्ध करने में मदद करें, क्योंकि अब आतिशी सवैंधानिक पद आसीन है।

उन्होंने कहा कि आतिशी को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अरविन्द केजरीवाल की तरह नौंटकी करने की बजाय दिल्ली की जनता के लिए काम करे। ध्वस्त पड़ी सड़क, सुरक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल व वायु प्रदूषण और लोगों को मौलिक सुविधाऐं देने के लिए काम करें, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को बदहाल और बर्बाद कर दिया है।

क्षमा मांग कर क्षमावाणी पर्व मनाया कृष्णा नगर जैन समाज ने समस्त प्राणी मात्र से

सुषमा रानी

नई दिल्ली। विश्वास नगर सी बी डी के हाल में कृष्णा नगर जैन समाज द्वारा हजारों जैन धर्म अनुयायियों और भक्तो के उमड़े जनसमूह में जैन धर्म के महान संत प्रसिद्ध जीवन है पानी की बूंद महाकाव्य के मूल रचियता विमर्श लिपि के स्रजेता राष्ट्रीय योगी संत श्री 108 विमर्श सागर महामुनि राज के मंगल सानिध्य दशलक्षण पर्व की महाबेला पर सम्मान समारोह एवम क्षमावाणी महापर्व यमुनापार में पहली बार इतना विशाल समस्त जैन समाज द्वारा आयोजित किया गया।

यहां विवान हॉल में आयोजित इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र जैन और समाज सेवी टीनू जैन ने स्थल पर आए मीडिया पर्सन को बताया केंद्रीय मंत्री एम सांसद हर्ष मल्होत्रा सहित कई नेताओ ने आचार्य विमर्श सागर महामुनि राज से आशीर्वाद लिया। नरेंद्र जैन और टीनू जैन के अनुसार मुनिराज विमर्श सागर महाराज अपने पच्चीस वर्षीय संयमी जीवन में देश के अलग अलग कोने में अस्सी हजार से ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा करके जनमानस में अहिंसा, शाकाहार, व्यसन मुक्ति और देश भक्ति की अलख जगाने का पुनीत कार्य कर रहे है। यहां उमडी हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए महामुनि राज विमर्श सागर जी ने कहा क्षमा को सुशोभित कीजिए ,जीवन में बैर की खाई नहीं क्षमा का भवन तैयार करें। महामुनि राज ने कहा क्षमा शब्द मानवीय जीवन की आधार शिला है, दस लक्षण पर्व हमें यही सीख देता है कि क्षमावाणी के दिन हमें अपने जीवन से सभी तरह के बैर भाव-विरोध को मिटा कर प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए और हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए, यही क्षमावाणी है, इस अवसर पर संगीत और भक्तिपूर्ण नृत्य का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। आयोजको द्वारा सात्विक भोजन प्रसाद का भी प्रबन्ध किया गया।

केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने किया 2 मेडिकल मोबाइल डिस्पेंसरी वैनों का शुभारंभ.....

दिलीप देवतवाल

नई दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रारंभ सेवा पखवाड़ा के तहत एवं छात्र नेता स्व. विवेक बिधूड़ी जी की 43वीं जयंती के शुभावसर पर तुगलकाबाद विधान सभा क्षेत्र स्थित चुंगी न0-2 लाल कुआ, पुल प्रहलादपुर में विवेक बिधूड़ी फांउडेशन व ओ.एन.जी.सी. द्वारा 2024-25 वित पोषित सी.एस.आर. योजना के अंतर्गत दो निःशुल्क मेडिकल मोबाइल डिस्पेंसरी वैनों का आज माननीय कानून, न्याय, संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी व दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी द्वारा विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर माननीय केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि देश में मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएँ हर क्षेत्र में गरीब, मजदूर, किसान, दलित, युवाओं के जीवन स्तर में बदलाव ला रही हैं। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों के विषय में बताया।

पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि 17 सितंबर मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिवस से 02 अक्टूबर महात्मा गांधी जी व श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक 15 दिन हमें गरीब, मजदूर व जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का अवसर मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देशभर में लोगों की सेवा कर इसे सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। बिधूड़ी ने बताया कि सेवा पखवाड़े के प्रथम दिन दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के तीन बड़े सरकारी अस्पताल ई.एस.आई ओखला फेस-1, आयुर्वेद अस्पताल बदरपुर और टी.बी. अस्पताल महरौली जहाँ हजार की संख्या में भर्ती इन अस्पतालों में गरीब रोगियों को फल वितरित किए गए और सेवा पखवाड़े के दूसरे दिन तुगलकाबाद गाँव में जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जहाँ सैंकड़ो की संख्या में लोगों ने सेवा के रूप में रक्तदान किया जो कि अस्पतालों में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों व गरीब मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर दिया जा सके। इसी क्रम में आज झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में संचालित 2 मेडिकल वैन सप्ताह में 6 दिन प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और 2:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक प्रत्येक दिन अलग-अलग स्थानों पर झुग्गी-बस्तियों, लाल कुआं चुंगी न0-2, प्रेम नगर, इन्दिरा कल्याण विहार ओखला फेस-1, बंगाली कॉलोनी तुगलकाबाद गाँव, रेलवे चैक हरकेश नगर, संजय कॉलोनी व अन्य कैम्प ओखला फेस-2, गोला कुआ कैम्प, तेखण्ड गाँव, वी.पी.सिंह कैम्प तुगलकाबाद, सोनिया गाँधी कैम्प, नवजीवन व ट्रांजिट कैम्प गोविन्दपुरी, अमृतपुरी व दयाल सिंह कैम्प श्रीनिवासपुरी, शहीद कैम्प दक्षिणपुरी आदि क्षेत्रों में रहने वाले गरीब जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाईयाँ व स्वास्थ्य जांच आदि चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करेंगी।

दिल्ली में दो दिन बाद लागू होगा 'विंटर एक्शन प्लान', गोपाल राय ने 'वर्क फ्रॉम होम' को लेकर बताई योजना

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने कहा कि हम 25 सितंबर से विंटर एक्शन प्लान लागू करने जा रहे हैं। पहले यह 26 सितंबर के लिए निर्धारित थी। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम की सुविधाएं देने के साथ-साथ ऑफिस जाने के लिए समय में बदलाव को भी प्लान में शामिल किया गया है।

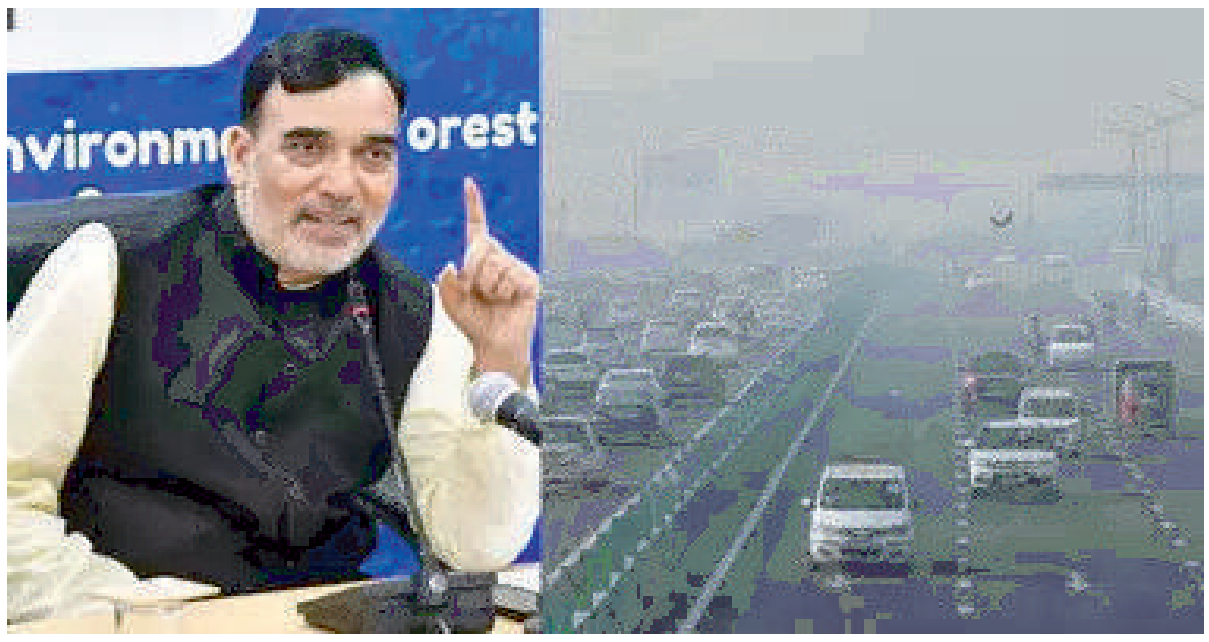

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार संभाला और नई सरकार के फोकस और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में नया मंत्रिमंडल केजरीवाल के कामों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान शहर में प्रदूषण को रोकना इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है।

गोपाल राय ने कहा, ₹हम अरविंद केजरीवाल सरकार तैयार सभी लंबित परियोजनाओं को पूरा करेंगे और स्वच्छ, हरित और बेहतर दिल्ली के निर्माण के लिए नई पहल करेंगे। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना है। सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करेगी। हमने इस बारे में अनुभवी विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ गोलमेज चर्चा की। अधिकांश विभागों ने विंटर एक्शन प्लान पर अपने इनपुट दिए हैं। हम सुझावों और सिफारिशों को पुख्ता करने के लिए जल्द ही दिल्ली के मुख्य सचिव से मिलेंगे।₹

हम 25 सितंबर से विंटर एक्शन प्लान लागू करेंगे: गोपाल राय

उन्होंने कहा, "हम 25 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान लागू करने जा रहे हैं। पहले यह 26 सितंबर के लिए निर्धारित थी।" उन्होंने कहा कि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम की सुविधाएं देने के साथ-साथ ऑफिस जाने के लिए समय में बदलाव को भी प्लान में शामिल किया गया है। जल्द ही इसके प्रावधान भी लागू किए जाएंगे।"

विपरित परिस्थितियों में आतिशी बनीं दिल्ली की सीएम: गोपाल राय

गोपाल राय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में केजरीवाल के लिए एक कुर्सी खाली रखने के मुख्यमंत्री आतिशी के फैसले का भी समर्थन किया। उन्होंने जनता की अदालत में 'निर्दोष' साबित होने तक कुर्सी छोड़ने के अरविंद केजरीवाल के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, "हर कोई जानता है कि आतिशी ने बेहद विपरीत परिस्थितियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाला था।"

हमारा ध्यान लंबित परियोजनाओं को पूरा करने पर: गोपाल राय

गोपाल राय ने यह भी कहा, ₹फिलहाल टीम केजरीवाल का मुख्य ध्यान लंबित परियोजनाओं को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी जन कल्याण लाभ और सुविधाएं शहर के निवासियों तक पहुंचती रहे।₹ उन्होंने कहा, ₹चुनाव तक प्रगति कार्य को निर्बाध रूप से जारी रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी टीम इसे सफल बनाएगी।₹

इन 21 फोकस बिंदु पर काम करेगी सरकार

हाट स्पॉट की ड्रोन के द्वारा निगरानी
प्रदूषण को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन
धूल प्रदूषण पर नियंत्रण
मोबाइल एंटी स्मॉग गन का संचालन
वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण
पराली प्रदूषण
ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली एप
औद्योगिक प्रदूषण
हरित क्षेत्र को बढ़ाना/ वृक्षारोपण
रियल टाइम सोर्स अपार्शन्मेंट स्टडी
ई-वेस्ट इको पार्क
पटाखों पर प्रतिबंध
जन भागीदारी
केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद
हरित रत्न पुरस्कार
ग्रेप का क्रियान्वयन
ओपन कूड़ा बर्निंग
वर्क फ्रॉम होम
स्वैच्छिक रूप से निजी वाहनों पर अंकुश लगाना
ऑड-इवेन की तैयारी
कृत्रिम वर्षा

चलों - चलों, माँ चामुंडा के दरवार चलों : पोला भाई ग्रुप

3अक्टूबर से माँ चामुंडा देवी मंदिर राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर आयोजित किया जायेगा 32वा विशाल मेला
सभी शहरवासी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं : पोला भाई ग्रुप

आगरा। हर साल की भांति इस साल भी नवरात्रि के शुभ अवसर पर दैनिक यात्री व व्यापारी संघ पोलाभाई ग्रुप द्वारा मां चामुंडा देवी का 32वा विशाल मेला मां चामुंडा देवी मंदिर राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अक्टूबर चलेगा। आज भूमि पूजन करके भव्य आयोजन का आगे का कार्य प्रारंभ किया गया।

इस शुभ अवसर पर दैनिक यात्री एवं व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय वर्मा उर्फ़ पोला भाई ने पत्रकार वार्ता में सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि मातारानी की कृपा से 32वा भव्य मेला मां चामुंडा देवी मंदिर राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर 3 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जो 13 अक्टूबर चलेगा। इस भव्य मेले में हजारों श्रद्धालु आते हैं और आरती के बाद आशीर्वाद और प्रसाद ग्रहण करते हैं। मां चामुंडा देवी सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती हैं। अतः आप अपना कीमती समय निकालकर मां चामुंडा देवी का आशीर्वाद और प्रसाद लेने और अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने जरूर आए। माँ चामुंडा देवी के 32वे भव्य मेले में सभी शहरवासी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। इस मेले में माँ वैष्णो देवी की तरह गर्भ जून गुफा के दर्शन प्राप्त होंगे तथा सभी भक्त गर्भ जून गुफा के दर्शन करके माँ वैष्णो देवी के जैसा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सभी देशवासियों पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। इस पुण्य कार्य में बढ़-चढ़कर भाग लेने वाले सभी सराहनीय सहयोगियों का बहुत - बहुत आभार। जय बाबा की। जय माता दी।

इस दौरान हेमंत प्रजापति, शरद चौहान, विक्रांत सिंह, मुरारी लाल गोयल, संतोष अग्रवाल, अमित पटेल, राजेश प्रजापति, हरिशंकर उपाध्याय, कुंदनिका शर्मा, आशु जैन, पोला भाई, पप्पू भाई, अरविंद उपाध्याय, राजा शर्मा, राज ठाकुर, पंडित सचिन दीक्षित, मुकेश शर्मा, बीपी चौहान, लालू भाई, निक्कू पंडित, राम मोहन शर्मा, हनी पंडित, यतिन चोपड़ा, अभिषेक, यश उपाध्याय, देवसाग़र सिंह, उमेश, सौरभ, टिल्लू, नंदू आदि लोग उपस्थित रहे।

उपचुनाव में वोट नहीं करेंगे गाजियाबाद की इस सोसायटी के लोग, बहिष्कार की बताई वजह

गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में गौर सिद्धार्थम सोसायटी (Gaur Siddhartham Society) के निवासियों ने टूटी सड़कों नालियों और गंगाजल की आपूर्ति न होने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आगामी विधानसभा उपचुनावों में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आवास विकास अधिकारी समस्याओं के समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं।

गुरुग्राम। गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार की गौर सिद्धार्थम सोसायटी वासियों ने टूटी सड़क, नाली और गंगाजल की आपूर्ति न होने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय निवासियों का कहना था कि आवास विकास अधिकारी समस्याओं के समाधान के नाम पर आश्वासन दे रहे हैं।

सड़कों में गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। यहां के लोगों ने आगामी विस उपचुनाव को लेकर बहिष्कार का ऐलान किया है। गौर सिद्धार्थम सोसायटी के निवासियों ने काफी संख्या में एकजुट होकर रविवार को पट्टिकाएं लेकर प्रदर्शन किया।

कब मिलेगी गंगाजल वाटर सप्लाई?

इन पर लिखा था सड़क और नाली कब तक, गंगाजल वाटर सप्लाई कब मिलेगी। उनका कहना था कि आवास विकास परिषद में अधिकारियों के अलावा जिलाधिकारी और शहर के विधायक से सांसद बने अतुल गर्ग से वह कई बार मिलकर समस्याओं से अवगत करा चुके हैं, लेकिन सभी ने आश्वासन के अलावा गंभीरता के साथ समस्याओं का समाधान नहीं कराया।

स्थानीय निवासी अरुण सिंह ने कहा कि सिद्धार्थ विहार में अधिकांश सड़कों का निर्माण हो गया, लेकिन सोसायटी को कनेक्ट करने वाली सड़क को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। मजबूरन अब हम लोग विधानसभा उपचुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे।

क्या बोले सोसायटी के लोग?

सड़क निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलकर समस्याओं से अवगत करा चुके हैं। इस संबंध में कई बार डीएम और आवास विकास अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए, लेकिन सड़कों का हाल बदहाल है। सड़कों में गड्ढे हैं और नाली नहीं हैं। खुले दिनों में धूल और वर्षा में गड्ढों में पानी भरने से हादसे का खतरा रहता है। - अरुण सिंह, गौर सिद्धार्थम सोसायटी

पीने के लिए गंगाजल की आपूर्ति का कई बार आश्वासन मिल चुका है, लेकिन अभी तक आपूर्ति नहीं की गई। सोसायटी के बाहर खुले में कूड़े के ढ़ेर लगे हैं। नगर निगम और बाहरी लोग यहां कूड़ा डालकर चले जाते हैं, जिसका विरोध करने पर लड़ाई झगड़े पर उतारु होते हैं। शिकायत के बावजूद कहीं कोई हल नहीं निकल रहा है। - अविनाश सिंह, गौर सिद्धार्थम सोसायटी

सड़कें टूटी हैं यहां सार्वजनिक परिवहन सेवा की सुविधा आज तक लोगों को उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहां लोग अपनी सवारी के अलावा ई-रिक्शा के भरोसे हैं। यहां जगह-जगह अतिक्रमण किया गया है। पार्क बनाने का दावा किया गया था, लेकिन यहां झुग्गी-झोपड़ी और असमाजिक तत्वों का डेरा है।

- शशांक मिश्र, गौर सिद्धार्थम सोसायटी

आवास विकास की बड़ी लुभावानी योजनाओं को देखकर यहां लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई का एक घर के लिए निवेश किया था। 40 एकड़ में थीम पार्क का सपना दिखाया गया। सड़कों पर अंधेरा, सुविधा के नाम पर बैंक, पोस्ट आफिस, पेट्रोल पंप, सीएनसी स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, अस्पताल नहीं है। लोगों को इन कार्यों के लिए इंदिरापुरम, प्रताप विहार और गाजियाबाद जाना पड़ता है। - एनके नेगी, प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ विहार

सफाई कर्मचारियों का ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन, यातायात प्रभावित; लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानी

नोएडा के सेक्टर फेस-1 में सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दलित प्रेरणा स्थल पर उनका धरना-प्रदर्शन जारी है जिससे सड़क पर जाम लग गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सफाई कर्मियों के धरना प्रदर्शन के चलते रोड पर जाम की स्थिति बन गई है जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।

गुरुग्राम। नोएडा। नोएडा में सेक्टर फेस-1 में सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दलित प्रेरणा स्थल पर सफाई कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन जारी है।

वहीं, सफाई कर्मियों के धरने के चलते रोड पर जाम की स्थिति बन गई है और इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

सफाई कर्मचारियों के विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। नोएडा के सेक्टर फेस-1 थाना क्षेत्र के दलित प्रेरणा स्थल पर सफाई कर्मचारियों का धरना-प्रदर्शन चल रहा है।

शिक्षक के घर पर छापेमारी, टीम को मिले अहम दस्तावेज और...; 10 घंटे से कार्रवाई है जारी

गाजियाबाद में एक कॉलोनी में एक शिक्षक घर पर छापेमारी की गई। वहीं छापा पड़ते ही परिवार के सदस्यों में हड़कंप मच गया। करीब 10 घंटे से छापेमारी की कार्रवाई जारी है और टीम को घर से कुछ अहम दस्तावेज व नकदी और जेवरात मिले हैं। इस किसी को भी बाहर या अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।

गाजियाबाद। Raid in Ghaziabad यूपी के गाजियाबाद में जांच एजेंसी की टीम ने प्रताप विहार की भाऊराव देवरस कॉलोनी में रहने वाले एक शिक्षक के घर पर छापा मारा। लगभग 10 घंटे से अधिक समय से छापेमारी की कार्रवाई जारी है, इस दौरान किसी की भी न तो घर में जाने दिया जा रहा है न ही घर से बाहर जाने दिया जा रहा है। शिक्षक के घर के पास पुलिस की भी तैनाती की गई है।

कॉलोनी में 12 साल पहले आए थे शिक्षक

कॉलोनी के कुछ लोगों ने बताया कि शिक्षक योगेश्वर मिश्रा परिवार के साथ भाऊराव देवरस कॉलोनी में लगभग 12 साल पहले रहने के लिए आए थे। उन्होंने भवन संख्या 333 में पहले प्रथम तल का फ्लैट खरीदा था, इसके कुछ साल बाद भूतल भी खरीद लिया। उनके बेटे कारोबारी हैं, वह अक्सर शहर के बाहर आते-जाते रहे हैं।

स्थानीय पुलिस भी है साथ

हालांकि, वे किस कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में कॉलोनी के लोगों को स्पष्ट तौर पर जानकारी नहीं है। रविवार सुबह आठ बजे के करीब तीन कारों में जांच एजेंसी की टीम योगेश्वर मिश्रा के घर पहुंची, जांच टीम में महिला अधिकारी भी शामिल हैं। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची।

टीम ने कब्जे में लिए अहम दस्तावेज

सूचना है कि इस दौरान घर से नकदी, जेवरात सहित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच एजेंसी की टीम ने कब्जे में लिए हैं, परिवार के सदस्यों से उनके बारे में पूछताछ की गई है। जांच करने आई टीम के सदस्यों ने अपने विभाग और जांच से जुड़ी किसी भी जानकारी को देने से मना कर दिया है।

हालांकि, एक सूत्र ने बताया कि टीम दिल्ली के इनकम टैक्स आफिस से यहां पर जांच के लिए आई है। देर शाम तक शिक्षक के घर पर छापेमारी जारी है।

क्या है पूर्व मंत्री के गांव का हाल? ग्रामीण इन मुद्दों पर देंगे वोट; रखी ये बड़ी मांग

Haryana Vidhansabha Election 2024 हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक ही है। लेकिन चुनाव से पहले ग्रामीणों ने अपने-अपने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दैनिक जागरण के संवाददाता ने पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह के गांव फाजिलपुर का जायजा लिया तो पता चला कि यहां 12वीं तक स्कूल ही नहीं है। ग्रामीणों की मांग है कि गांव में 12वीं तक स्कूल जरूर बनना चाहिए।

गुरुग्राम। इस चुनाव में दिग्गजों के गांव की क्या तस्वीर है, क्या महौल है, क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों पर यहां के लोग वोट करेंगे, इसको लेकर दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता ने पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह के गांव फाजिलपुर में पहुंच कर जायजा लिया। इस दौरान जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई वह है गांव में 12वीं तक के सरकारी स्कूल का न होना। पेश है रिपोर्ट...

राजीव चौक से पांच किलोमीटर दूर सोहना रोड पर पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह का फाजिलपुर गांव है। राव नरबीर इस बार बादशाहपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। बादशाहपुर क्षेत्र के इस गांव में भी दोतरफा माहौल है। कई लोग जहां भाजपा को वोट देने के पक्षधर हैं तो कई कांग्रेस के साथ हैं।

ग्रमीणों ने बताए अपने मुद्दे

गांव के शुरुआत में मंदिर के पास चौपाल में बैठे कुछ लोगों से मुद्दे जाने गए। नितिन यादव कहते हैं यहां सफाई व्यवस्था बेहतर है। लेकिन वर्षा के दिनों में गांव में ढाई फीट तक जलभराव हो जाता है। उन्होंने गांव में शिक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल उठाया।

गांव में नहीं है 12वीं तक का स्कूल

उन्होंने कहा कि गांव में 12वीं तक सरकारी स्कूल नहीं है। अपर मीडियम क्लास के लोग अपने बच्चों को तो प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं, लेकिन गांव में बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग रहते हैं, जो बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पलड़ा और बादशाहपुर भेजना पड़ता है।

हंस कुमार कहते हैं कि सरकार वह अच्छी है जो रोजगार दे, शिक्षा दे। गांव में विकास के कार्य कई हुए हैं। यहां अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग रह रहे हैं। अब लोगों के घर कच्चे नहीं, बल्कि सात-सात मंजिला इमारतें बन गई हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं तो हर गांव में लगी रहती हैं।

वहीं, हरदीप यादव ने बताया कि गांव में घरों के आगे तारों का जाल बिछा हुआ है। इससे हर समय खतरा बना रहता है। नरबीर सिंह 15 से 20 दिनों में गांव का एक बार चक्कर लगाते हैं।

अनियंत्रित विकास, सफाई-व्यवस्था दुरुस्त नहीं

लोगों के मुताबिक, फाजिलपुर गांव की आबादी 17 सौ के करीब है। किंतु यहां दूसरे प्रदेश से आने वाले 30 हजार से ज्यादा लोग किराए पर रहते हैं। कई किराएदार वर्षों से रह रहे हैं, इसलिए इनकी भी वोट बनी हुई है। अब गांव में दो हजार से ज्यादा मतदाता हैं। ये वोटर किसी भी प्रत्याशी की जीत-हार का अंतर बढ़ा सकते हैं।

गांव में विकास तो हुआ, लेकिन नियोजित तरीके से नहीं हो पाया। यहां कोई गली आठ फीट की संकरी है तो कहीं पर 20 फीट का रास्ता दिया गया है। साफ-सफाई न होने और घरों के बाहर तारों के जाल से भी लोग परेशान हैं।

'तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम में' 'पशुओं की चर्बी बरामद'

विजय कुमार

आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के 'तिरुमाला' शहर में 'तिरुपति बालाजी मंदिर' देश के सर्वाधिक अमीर मंदिरों में से एक है। यहां प्रतिवर्ष देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु करोड़ों रुपए चढ़ावा चढ़ाते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण के अधीन यह मंदिर...

आंध्र प्रदेश में तिरुपति जिले के 'तिरुमाला' शहर में 'तिरुपति बालाजी मंदिर' देश के सर्वाधिक अमीर मंदिरों में से एक है। यहां प्रतिवर्ष देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु करोड़ों रुपए चढ़ावा चढ़ाते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण के अधीन यह मंदिर 'तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम' (टी.टी.डी.) द्वारा संचालित है जिसके प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार करती है। इस मंदिर में भगवान को पवित्र लड्डू प्रसादम का भोग लगाने की प्रथा लगभग 300 वर्ष पुरानी है। तिरुपति बालाजी में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डुओं को 'महाप्रसादम' कहा जाता है। इन्हें ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी के खजाने से आया माना जाता है। लगभग 4 दशक पूर्व तक इस प्रसाद की पवित्रता और गुणवत्ता को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठा था। पहली बार 1985 में एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसके खरीदे हुए लड्डू प्रसादम में फफूंद और कील निकली थी।

अब एक बार फिर यहां का 'लड्डू प्रसादम' विवादों में घिर गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू ने 18 सितम्बर, 2024 को आरोप लगाया कि ''राज्य की पिछली 'वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी' की जगन मोहन रैड्डी सरकार के शासनकाल में यहां बनने वाले 'लड्डू प्रसादम' में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया।'' ''केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एन.डी.डी.बी. (नैशनल डेयरी डिवैल्पमैंट बोर्ड) की एक 'काल्फ रिपोर्ट' के अनुसार 'वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी' के शासन के दौरान पवित्र तिरुपति लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। गाय के घी में सोयाबीन, लोबिया, जैतून, गेहूं, मक्का, कपास, मछली का तेल, गाय के मांस के तत्व, ताड़ का तेल और सूअर की चर्बी है।''

तेदेपा प्रवक्ता 'अनम वेंकटरमण रैड्डी' ने दावा किया है कि' 'गुणवत्ता वाले घी की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो से अधिक है जबकि 'वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी' की सरकार ने 320 रुपए किलो के भाव पर निविदाएं आमंत्रित कीं। रिश्वत खाने के लिए 15000 किलो घी का टैंडर दिया गया।'' तेदेपा नेता 'पट्टभि राम कोमारैड्डी' ने आरोप लगाया है कि ''2019 से 2024 के बीच मुख्यमंत्री जगन मोहन रैड्डी ने अपने ही चाचाओं वाई.वी. सुब्बा रैड्डी तथा करुणाकर रैड्डी को टी.टी.डी. का अध्यक्ष नियुक्त कर टी.टी.डी. फंड की लूट शुरू कर दी।'' 19 सितम्बर, 2024 को तेदेपा प्रवक्ता 'अनम वेंकटरमण रैड्डी' ने एक संवाददाता सम्मेलन में कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट दिखाई जिसमें दिए गए घी के नमूने में गाय की चर्बी की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी। इसमें लार्ड (सूअर की चर्बी) और मछली के तेल की मौजूदगी का भी दावा किया गया है।

जहां तेदेपा ने 'वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी' पर तिरुमाला के पवित्र मंदिर के लड्डू प्रसादम में अपवित्र वस्तुओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया है वहीं वाई.एस.आर.सी.पी. के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वाई.वी. सुब्बा रैड्डी ने इसका खंडन किया था और आरोप लगाया था कि' 'चंद्र बाबू नायडू ने तिरुमाला के मंदिर व करोड़ों हिन्दुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का महापाप किया है।'' परंतु अब 20 सितम्बर को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारी जे. श्यामलराव ने (घटिया घी के इस्तेमाल की स्वीकारोक्ति करते हुए) कहा है कि ''मंदिर को घी की आपूर्ति करने वालों ने मंदिर में मिलावट की जांच संबंधी सुविधा न होने का लाभ उठाया। प्रयोगशाला में चुने हुए नमूनों में पशु चर्बी और लार्ड (सूअर की चर्बी) की मौजूदगी का पता चला है।'' जे. श्यामलराव की स्वीकारोक्ति से जहां मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू का आरोप सच साबित हो गया है वहीं उन्होंने घी की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को काली सूची में डालने के साथ ही जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा भी की है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। इस कृत्य में शामिल होने वालों को कड़ी सजा देने की जरूरत है। अशुद्ध प्रसाद ग्रहण करने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं ही आहत नहीं हुईं बल्कि ऐसे प्रसाद का सेवन हानिकारक भी सिद्ध हो सकता था।

बदले हुए हालात और आतंकवाद के कारण पाक-भारत सिंधु जल संधि में बदलाव की जरूरत

1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू तथा पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का तथा पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और जेहलम का नियंत्रण प्राप्त हुआ था। जनवरी, 2023 से लेकर अब 30 अगस्त को चौथी बार पाकिस्तान को नोटिस जारी करके भारत सरकार ने 1960 की 'सिंधु जल संधि' (आई.डब्ल्यू.टी.) पर पुनर्विचार और बदलाव की मांग को तेज कर दिया है और इस मामले में पाकिस्तान के बातचीत के लिए सहमत होने तक 'स्थायी सिंधु आयोग' (पी.आई.सी.) की सभी बैठकों को स्थगित करने की घोषणा कर दी है।

इस बदलाव के कारणों में जनसंख्या में बदलाव, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और भारत के उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास में तेजी लाना शामिल है। भारत ने इसके पीछे सीमा पार से जारी आतंकी गतिविधियों को भी कारण बताया है और कहा है कि इसके परिणामस्वरूप संधि के सुचारू तरीके से संचालन में बाधा आ रही है। भारत ने कहा है कि 1960 के बाद से हालात काफी बदल चुके हैं। किसी समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पानी सांझा करने के समझौते का एक आदर्श मॉडल मानी जाने वाली इस प्रक्रिया के रुकने के बाद भारत सरकार ने यह मांग की है। वर्तमान युग में भी इस संधि के सिद्धांत मजबूत रहे हैं और भारत ने इसी संधि के अंतर्गत 2007 में 'बगलिहार बांध परियोजना' तथा 2013 में पाकिस्तान के 'नीलम घाटी प्रोजैक्ट' के दो बड़े विवाद जीते हैं। 'किशनगंगा' और 'रतले परियोजनाओं' पर विवाद निपटारे का मुद्दा 2016 से पाकिस्तान द्वारा एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग और स्थायी मध्यस्थता अदालत (पी.सी.ए.) में भी जाने की मांग के बाद गंभीर होता गया है।

इस मामले में 'इंटरनैशनल वाटर ट्रीटी' (आई.डब्ल्यू.टी.) के सह-हस्ताक्षरकत्ता और गारंटर विश्व बैंक ने इस मामले में दो समानांतर प्रक्रियाओं को एक साथ चलने दिया जिसके लिए विश्व बैंक को पछताना पड़ सकता है। इस मामले में पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रक्रिया को नजरअंदाज करने तथा भारत द्वारा हेग में पी.सी.ए. की सुनवाई का बहिष्कार किए जाने से मामला और अधिक बिगड़ गया। पाकिस्तान ने 'इंटरनैशनल वाटर ट्रीटी' पर पुनर्विचार तथा बातचीत के लिए भारत के नोटिसों पर ठंडा रुख दिखाया है तथा मोदी सरकार द्वारा सभी स्थायी इंडस कमीशन बैठकों को रोकने के निर्णय ने इस प्रक्रिया के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। अतीत के विपरीत जब 'इंटरनैशनल वाटर ट्रीटी' से जुड़े मुद्दों को राजनीति से दूर रखा जाता था, अब दोनों ही पक्ष इस मामले पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। वर्ष 2016 के उड़ी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते' शायद इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है।

यह संयोग नहीं है कि यह घटनाक्रम भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों के टूटने के साथ मेल खाता है। न तो कोई राजनीतिक संवाद हो रहा है और न ही व्यापार। यही नहीं, 2021 का एल.ओ.सी. संघर्षविराम समझौता भी बढ़ते आतंकवादी हमलों तथा भारतीय सेना के जवानों की शहादत के बाद खतरे में है। हो सकता है कि संधि वार्ता फिर से शुरू हो सके, लेकिन किसी समझौते पर पहुंचना और भी कठिन होगा। अब सबकी नजरें पाकिस्तान सरकार द्वारा 15-16 अक्तूबर को होने वाली एस.सी.ओ. सरकार प्रमुखों की बैठक के लिए भेजे गए निमंत्रण को लेकर नई दिल्ली की प्रतिक्रिया पर हैं। यह बैठक निश्चित रूप से इस मामले में आगे की वार्ता के संदर्भ में विशेष महत्व रखती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जलवायु परिवर्तन जैसे नए मुद्दे और सिंधु नदी पर अक्षय ऊर्जा और जल विद्युत विकल्पों की आवश्यकता 64 वर्ष पुरानी इस संधि को फिर से खोलने की मांग करती है। यह कैसे किया जाता है और वर्तमान विवादों का समाधान कैसे होता है, इससे तय होगा कि दोनों देश उस संधि को, जिसे अमरीकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावर ने एक बार 'एक बहुत ही निराशाजनक विश्व दृश्यपटल में एक चमकता बिंदू' कहा था, बचा सकते हैं या नहीं। अब यह तो समय ही बताएगा कि यह घटनाक्रम क्या रूप लेता है और भारत द्वारा संधि के नियमों में बदलाव का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

गाजियाबाद में प्रभारी मंत्री ने ई-रिक्शा चालकों को दिलाई भाजपा की सदस्यता

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के विजयनगर स्थित बीमा बाई पार्क के अंदर ई-रिक्शा चालकों द्वारा सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण, लोकसभा सांसद अतुल गर्ग एवं महानगर अध्यक्ष संदीप शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में जुटे ई-रिक्शा चालकों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भाजपा सरकार देश के हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम कर रही है। मोदी का लक्ष्य भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाना है और प्रदेश के मुखिया योगी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी दिन-रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी बिना किसी भेदभाव के समाज के हर जाति और धर्म के लोगों को सदस्यता अभियान से जोड़ रही है।

सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि जिनके पास कोई निश्चित आय नहीं है, चाहे वे ई-रिक्शा चालक हों या फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले लोग। उनके लिए सरकार सकारात्मक सोच के साथ उन्हें लाभ से जोड़ने के लिए तत्पर है।

भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा द्वारा स्थानीय रिक्शा चालकों से सदस्यता से जुड़ने का आह्वान करते ही समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने यहां जुटे रिक्शा चालकों को फोन नंबर 8800002024 बताया। उन्होंने सभी से अपना मोबाइल ऊपर उठाकर इसे डायल करने को कहा। इस दौरान सैकड़ों हाथ मोबाइल के साथ उपर उठे और लोगों ने नंबर डायल कर पार्टी की सदस्यता ली।

मंत्री असीम अरुण ने ई-रिक्शा चालकों से बात की और उनकी समस्याएं भी जानीं। कार्यक्रम के दौरान ई-रिक्शा चालक संगठन के पदाधिकारी, महामंत्री गोपाल अग्रवाल, संदीप त्यागी, पार्षद पूनम सिंह, ई-रिक्शा चालक आदि मौजूद रहे।

चाकण के अलावा कहीं और नया प्लांट नहीं लगा रही महिंद्रा, खबरों के साथ किया खंडन

परिवहन विशेष न्यूज

एसयूवी श्रेणी की बाजार हिस्सेदारी में 21.6 प्रतिशत राजस्व हासिल करने वाली एसयूवी विनिर्माता महिंद्रा एण्ड महिंद्रा चाकण में अपने आगामी इलेक्ट्रिक वाहन और ईवी बैटरी विनिर्माण संयंत्र की राह पर बढ़ रही है और उसने अपने नए ईवी आर्किटेक्चर के लिए अन्य इकाई की योजना से इंकार किया है।

पिछले महीने प्रमुख मीडिया समाचार बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित रिपोर्टों में कहा गया था कि केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव के अनुसार एमएंडएम के अधिकारी जल्द ही उनसे मिलने वाले हैं। राज्य विनिर्माण इकाइयों के लिए ईवी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। इससे पहले अगस्त में रॉयटर्स की खबर में बताया गया था कि महिंद्रा एण्ड महिंद्रा और चीन की शांक्सी ने गुजरात में कार विनिर्माण संयंत्र बनाने के लिए तीन अरब डॉलर का संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमति जताई है, जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है। अलबत्ता बाद में महिंद्रा एण्ड महिंद्रा ने स्पष्ट किया था कि यह खबर निराधार है।

हाल की रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि कंपनी महाराष्ट्र में शिरुर, अहमदनगर, चाकन आदि के पास एक और नए संयंत्र के लिए जमीन की तलाश कर रही है, जो एक बहु-ऊर्जा मंच - न्यू फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर (एनएफए) पर वाहन बनाएगी।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी (वाहन एवं कृषि क्षेत्र) राजेश जेजुरिकर ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'बैटरी संयंत्र और हमारे बोर्न ईवी (ऐसे वाहन जो शुरू से ही ईवी के रूप में बनाए जाते हैं) के लिए महाराष्ट्र के चाकण में हमारी ईवी इकाई आ रही है। इस इकाई के अलावा किसी नई ईवी इकाई की योजना नहीं है।'

एमएण्डएम की नजर साल 2030 तक अपने पोर्टफोलियो में 30 प्रतिशत ईवी की मौजूदगी पर है और वह इनग्लो ईवी प्लेटफॉर्म के तहत पांच ईवी की शुरुआत करेगी।

पिछले जनवरी में उसे महाराष्ट्र सरकार से चाकण में 10,000 करोड़ रुपये का ईवी संयंत्र लगाने की मंजूरी मिली थी और वह यह निवेश अगले सात से आठ साल में करेगी। साल 2029 तक चाकण इकाई में प्रति वर्ष 2,00,000 वाहनों का उत्पादन होगा। एमएण्डएम साल 2030 तक प्रति वर्ष 10 लाख वाहन बनाने की कुल क्षमता हासिल करने की योजना बना रही है। फिलहाल उसकी क्षमता प्रति वर्ष 8,00,000 वाहन है।

कंपनी ने कहा है कि वह अपनी एसयूवी उत्पादन क्षमता को प्रति माह 49,000 (वित्त वर्ष 24 के अंत में) से बढ़ाकर वित्त वर्ष 25 के अंत तक प्रति माह 64,000 करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसे वित्त वर्ष 2026 के अंत तक और बढ़ाकर प्रति माह 72,000 वाहन कर दिया जाएगा। इसलिए वित्त वर्ष 26 के अंत तक कुल क्षमता 8,64,000 वाहन हो जाएगी।

इनग्लो वाहन पोर्टफोलियो को इस अतिरिक्त क्षमता की जरूरत होगी। विश्लेषकों का मानना है कि एमएण्डएम को एनएफए प्लेटफॉर्म के लिए ज्यादा क्षमता की जरूरत होगी। एक विश्लेषक ने कहा चाकण में कंपनी प्रति वर्ष 2,00,000 वाहनों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से ईवी श्रेणी के तहत पहला उत्पाद साल 2025 तक बाजार में आ जाएगा।

रचना क्रिएशंस ने लॉन्च किए दो नए मॉडल

परिवहन विशेष न्यूज

जिस तरह से देश भर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां भी नए इनोवेशन के साथ बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं।

आंकड़ों की बात करें तो इस समय भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है जो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हिस्सेदारी है और अब इलेक्ट्रिक वाहनों के सभी सेगमेंट लगातार शहरों से निकलकर गांवों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कारों से लेकर बैटरी ई-रिक्शा, ई-लोडर तक नए मॉडल अब गांवों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को रोजगार मुहैया कराने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज ग्रामीण परिवेश में आर्थिक रूप से अक्षम लोगों के लिए बैटरी रिक्शा रोजगार का साधन बन रहे हैं, वहीं इलेक्ट्रिक ई-लोडर भी परिवहन का एक अच्छा और सस्ता साधन उपलब्ध कराकर छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायियों के लिए एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं।

इसी क्रम में इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी रचना क्रिएशंस ने लखनऊ के अयोध्या रोड स्थित डॉल्फिन क्लब में दो नए मॉडल लॉन्च किए, जिसमें प्रदेश भर के इलेक्ट्रिक वाहन डीलर मौजूद रहे।

कंपनी के निदेशक विवेक सिंह, अभय सिंह और रणविजय सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि उनकी कंपनी रचना क्रिएशंस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर सब्सिडी के आधार पर हर जिले में बैटरी ई-रिक्शा उपलब्ध कराएगी, साथ ही स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार के उद्देश्य से अधिक सक्षम लोगों को सब्सिडी के साथ ई-रिक्शा उपलब्ध कराएगी।

2030 तक ईवी के लिए 49% ज्यादा पैसा देने को तैयार होंगे लोग : अध्ययन में खुलासा

परिवहन विशेष न्यूज

लोगों में अभी भी इस बात को लेकर काफ़ी असमंजस है कि इलेक्ट्रिक कार खरीदें या नहीं। इलेक्ट्रिक कार न खरीदने की सबसे बड़ी वजह रेंज एंग्जाइटी बनी हुई है। रेंज और कम चार्जिंग स्टेशन की वजह से लोग अभी भी कम इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं। लेकिन एक सर्वे सामने आया है। सर्वे में बताया गया है कि साल 2030 तक ज़्यादातर लोग न्यू एनर्जी व्हीकल को ही एकमात्र विकल्प मानने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि 2030 तक ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के पक्ष में होंगे। हालाँकि, अभी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना उतना लचीला नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले सालों में ईवी खरीदना आसान हो सकता है।

नई कार खरीदने वाले ज़्यादातर लोग साल 2030 तक न्यू एनर्जी व्हीकल (इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन आदि) को ही एकमात्र विकल्प मानने को तैयार हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में यह बात सामने आई है। अर्बन साइंस और द हैरिस पोल के सर्वे से पता चलता है कि खरीदार पेट्रोल/डीज़ल वाहन की कीमत से 49 प्रतिशत ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन के लिए खर्च करने को तैयार होंगे।

फिलहाल भारत के प्रमुख शहरों और हाईवे पर 6,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं। 2027 तक यह संख्या बढ़कर एक लाख से ज्यादा हो सकती है। सर्वे में पता चला है कि ईवी सेगमेंट के लिए सरकार की सक्रिय नीतिगत पहलों के कारण भी सकारात्मक दृष्टिकोण है। इसमें कहा गया है कि भारत को ईवी सेक्टर में उन्नत तकनीक और उत्पादन पैमाने तक पहुंच हासिल करनी चाहिए, जिसमें चीन ने महारत हासिल कर ली है।

सर्वे के मुताबिक अवसर बढ़ रहे हैं लेकिन भारत के ईवी अभियान को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर जब इस सेक्टर में चीन के प्रभुत्व की तुलना की जाती है। सर्वे के निष्कर्षों से पता चला है कि चीन लिथियम-आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्बाध संचालन के लिए महत्वपूर्ण घटकों के उत्पादन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में अग्रणी है। इसमें कहा गया है कि इस विशेषज्ञता का लाभ उठाए बिना भारत की ईवी महत्वाकांक्षाओं को प्रासंगिक बने रहना कठिन हो सकता है।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने तय किये विकास लक्ष्य के साथ देशभर में डीलर नेटवर्क का विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

भारत के सबसे बड़े और अग्रणी ईवी निर्माताओं में से एक ठुकराल इलेक्ट्रिक के प्रमुख ब्रांड ठुकराल ई-रिक्शा और ई-ऑटो ने देशभर में अपने डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार करने की अपनी योजना का खुलासा किया है। इस कदम का उद्देश्य अपनी इलेक्ट्रिक रिक्शा रेंज के लिए एक गहरा और व्यापक सेवा क्षेत्र प्रदान करके अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना है। वर्तमान में इसके 615 से अधिक डीलरशिप संचालन में हैं और चालू वित्त वर्ष के अंत तक इसकी शोरूम संख्या को 1100 से अधिक करने की योजना है, जिसमें 500 नई डीलरशिप शामिल हैं। यह विस्तार भारत भर में अपने ग्राहकों द्वारा इस सेगमेंट और ब्रांड की बढ़ती बाजार मांग को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक पहल का हिस्सा है।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्रबंध निदेशक जितेंदर ठुकराल ने कहा, ₹जैसे-जैसे भारतीय ईवी बाजार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इलेक्ट्रिक तीन पहिया की मांग भी बढ़ रही है। आज इलेक्ट्रिक तीन पहिया का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा है और ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला की मांग को पूरा करने और लगातार विकसित हो रही नई तकनीकों के साथ बने रहने के लिए हम अपने वाहनों को दिन-प्रतिदिन लगातार अपडेट कर रहे हैं। जबकि यह विस्तार हमारी विकास रणनीति का एक हिस्सा है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों और व्यवसायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना और उन्हें बाजार में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद प्रदान करना है।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स ने अपनी स्थापना के बाद से ही ईवी उद्योग में अग्रणी प्रौद्योगिकी समाधान, बेहतर गुणवत्ता और शानदार प्रदर्शन की पेशकश की है और लाखों भारतीयों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने में मदद की है। नवाचार और स्थिरता पर हमारे फोकस ने हमें बाजार में अग्रणी बना दिया है और हमने अपने आरएंडडी विंग से लेकर आपूर्ति श्रृंखला, सर्विस नेटवर्क से लेकर असेंबली लाइन तक निरंतरता सुनिश्चित करके अपने सभी भागीदारों और ग्राहकों से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं।

ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स की निरंतर नवाचार और रणनीतिक विकास योजनाएँ देश भर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्थिरता को बढ़ावा देने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। अपनी पहुँच का विस्तार करके और गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि पर दोगुना ध्यान देकर कंपनी इलेक्ट्रिक तीन पहिया सेगमेंट में अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है।

भारत की अग्रणी कंपनी ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स अभिनव, पर्यावरण के अनुकूल और किफायती वाहनों के साथ शहरी परिवहन में क्रांति ला रही है। भारत भर में मजबूत उपस्थिति और 350 से अधिक टचपॉइंट्स के साथ, ठुकराल इलेक्ट्रिक गुणवत्ता, स्थायित्व और ग्राहक संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में अग्रणी के रूप में ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्रमुख ब्रांड ठुकराल ई-रिक्शा, ई-कार्ट, ई-ऑटो और ई-लोडर ने विश्वसनीयता और प्रदर्शन में मानक स्थापित किए हैं। प्रबंध निदेशक जितेंदर ठुकराल के रणनीतिक नेतृत्व और शोध एवं विकास में निरंतर निवेश के माध्यम से ठुकराल इलेक्ट्रिक अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने तथा ईवी क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।

बैंकिंग, बीमा और निवेश में करियर के अवसर

विजय गर्ग

बैंकिंग में करियर (पारंपरिक और निवेश) बैंकिंग छात्रों (शिक्षा की किसी भी स्ट्रीम से) के बीच सबसे महत्वपूर्ण करियर विकल्पों में से एक है क्योंकि यह अच्छी तरह से भुगतान वाला, सुरक्षित और स्टेटस वाला करियर है। किसी भी विषय से इच्छुक स्नातक विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रवेश पा सकते हैं। प्रौद्योगिकी-संचालित नए निजी बैंकों के उद्भव और अल्पकालिक ऋण व्यवसाय में वित्तीय संस्थानों के प्रवेश ने अधिक पेशेवरों की आवश्यकता पैदा की है। अब बैंक सोने और विदेशी मुद्रा गतिविधियों में व्यापार के अलावा प्रतिभूतिकरण व्यवसाय, क्रेडिट कार्ड, उपभोक्ता ऋण और आवास ऋण में व्यापक भूमिका निभा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा के आधार पर लिपिक और परिवीक्षाधीन अधिकारी पदों के लिए मुख्य रूप से स्नातकों की भर्ती करते हैं। हालाँकि, इंजीनियरों, डॉक्टरों, प्रौद्योगिकीविदों, वकीलों, पूर्व-रक्षा अधिकारियों आदि जैसे पेशेवरों को अखिल भारतीय परीक्षणों के माध्यम से वरिष्ठ पदों के लिए भर्ती किया जाता है। निजी क्षेत्र/विदेशी बैंक कैंपस भर्ती और साक्षात्कार के माध्यम से जूनियर पदों पर एमबीए, सीए, सीएफए आदि को लेना पसंद करते हैं। हालाँकि, वरिष्ठ पदों पर, वे अनुभवी बैंकरों को चुनते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी ऐसे पदों के लिए स्वाभाविक पसंद बन जाते हैं। शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अलावा बैंक आम तौर पर अच्छे संचार कौशल, अच्छे पारस्परिक कौशल, ग्राहकों से निपटने की क्षमता, सतर्क स्वभाव और उद्योग के बुनियादी ज्ञान की तलाश करते हैं। हालाँकि, प्रवेश स्तर से ऊपर के स्तर पर विदेशी या निजी क्षेत्र के बैंकों में शामिल होने के लिए किसी को परियोजना विश्लेषण, क्रेडिट मूल्यांकन कौशल, विशाल ऋण पोर्टफोलियो का प्रबंधन और विदेशी मुद्रा जैसे कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान बैंकिंग उद्योग में किसी के करियर के लिए लाभकारी हो सकता है। इन पारंपरिक बैंकिंग नौकरियों के अलावा, कोई निवेश बैंकर के रूप में भी बैंकिंग उद्योग में अपना करियर बना सकता है। एक निवेश बैंकर वह व्यक्ति होता है जो बाजार के रुझान, निवेश में शामिल जोखिम और प्रचलित आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करके किसी संगठन को धन जुटाने में मदद करता है। एक निवेश बैंकर सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें प्रतिभूतियों का समर्थन करना, स्टॉक और बॉन्ड का व्यापार करना, विलय और अधिग्रहण की सुविधा देना, ब्रोकर-डीलर संचालन को बनाए रखना और प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण, और स्टॉक जारी करने और प्लेसमेंट के संबंध में वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करना शामिल है। किसी भी निवेश से पहले नौकरी के लिए विस्तृत शोध कार्य की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए समर्पण, प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत और समर्पण आवश्यक है। एक कुशल निवेश बैंकर कंपनी के लिए उच्च रिटर्न दिला सकता है। एक अच्छा निवेश बैंकर बनने के लिए व्यक्ति को उत्साही, भावुक, सक्रिय और त्वरित निर्णय लेने वाला होना चाहिए और कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम होना चाहिए। बैंकों को हमेशा कुशल निवेश बैंकरों की आवश्यकता होती है, जो संगठन के विकास में अधिक योगदान दे सकें। वैश्वीकरण के साथ, निवेश बैंकिंग का दायरा व्यापक हो गया है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के लिए असंख्य अवसर इंतजार कर रहे हैं। वेतनमान और पारिश्रमिक अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्लर्कों को लगभग रु. 30,000 - रु. 35,000 जबकि अधिकारी रुपये में शुरू कर सकते हैं। 50,000 - रु. 70,000 प्रति माह वेतनमान। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भर्ती किए गए एमबीए, सीए और सीएफए जैसे पेशेवरों का वेतन अधिक हो सकता है। लेकिन निजी और विदेशी बैंकों द्वारा भर्ती किए गए कुछ पेशेवरों को लगभग रुपये तक का वेतन पैकेज दिया जाता है। 60,000 - रु.80,000 प्रति माह. जहां तक निवेश बैंकिंग का सवाल है, निवेश बैंकिंग के क्षेत्र में एक नौसिखिया प्रति माह 40,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच कहीं भी कमा सकता है। अनुभव के साथ, एक निवेश बैंकर को उच्च वेतन पैकेज मिल सकता है। पाठ्यक्रम विवरण और निवेश बैंकिंग के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थान निवेश बैंकिंग के क्षेत्र में पाठ्यक्रम निवेश बैंकिंग के क्षेत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कुछ संस्थानों द्वारा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी पेश किए जाते हैं। निवेश बैंकिंग में स्नातक कार्यक्रम के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 है। पोस्ट-ग्रेजुएशन के लिए संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएट होना जरूरी है। कई संस्थाओं द्वारा कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। कई संस्थान अब इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। कुछ प्रमुख संस्थान हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (आईसीएफएआई) (त्रिपुरा) प्रमाणित निवेश बैंकरों की सोसायटी, (हैदराबाद) बीमा क्षेत्र में करियर बीस के दशक की शुरुआत में भारतीय बीमा उद्योग के वैश्वीकरण और उदारीकरण ने सार्वजनिक - भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), सामान्य बीमा निगम (जीआईसी), और डाक जीवन बीमा - और निजी - दोनों की सक्रिय भागीदारी के साथ अभूतपूर्व विकास के द्वार खोले। ओम कोटक महिंद्रा, बिड़ला सन-लाइफ, टाटा एआईएफ लाइफ, रिलायंस, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ-इंश्योरेंस कंपनी, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ, रॉयल सुंदरम, चोलामंडलम, इफको टोक्यो और टाटा एआईजी - जीवन और कमोडिटी बीमा व्यवसाय के क्षेत्र में काम करते हैं। कुछ वर्षों में अपनी तीव्र वृद्धि के कारण यह क्षेत्र न केवल राष्ट्र के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, बल्कि राष्ट्र के युवा और ऊर्जावान युवाओं के लिए हजारों रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद कर रहा है। बीमा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उम्मीदवारों को एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। न्यूनतम योग्यता 10+2 या समकक्ष वाले छात्र इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। भारतीय बीमा संस्थान बीमा सेवाओं के लिए लाइसेंसधारी, एसोसिएटशिप और फ़ेलोशिप और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इस प्रशिक्षण से गुजरने के बाद कोई भी इस क्षेत्र में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। किसी भी विषय में स्नातकोत्तर को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भर्ती किया जा सकता है जबकि स्नातक बीमा कंपनियों में विकास अधिकारी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जो लोग एक्चुरियल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित हैं, वे बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं, जिनके पास क्षेत्र में अपने अच्छे काम के कारण कंपनी का कर्मचारी बनने का अच्छा मौका है। बीमा एजेंसियां वास्तविक नुकसान तक पहुंचने और बीमाधारक द्वारा किए गए झूठे दावे से बचने के लिए बीमा सर्वेक्षणकर्ताओं के रूप में मैकेनिकल इंजीनियरों और डॉक्टरों जैसे स्वतंत्र पेशेवरों को भी नियुक्त करती हैं। सहायक, टाइपिस्ट, मशीन ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, टेलीफोन ऑपरेटर, क्लर्क आदि के पद 18 से 25 वर्ष की आयु के स्नातकों और 10+2 के लिए खुले हैं। बीमा उद्योग में वेतनमान और अन्य पारिश्रमिक सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में वेतनमान प्रत्येक पद के आधार पर सरकारी नियमों के अनुसार होता है। हालाँकि, निजी क्षेत्र में, वेतन पैकेज अधिक आकर्षक होते हैं, विशेष रूप से विपणन और बिक्री के क्षेत्रों में काम करने वाले प्रबंधन स्नातकों के लिए, जिनका प्रारंभिक वेतन रु. 30,000 से रु. 40,000 प्रति माह. जबकि कमीशन बीमा एजेंटों को दिए जाने वाले मुआवजे का सबसे सामान्य रूप है। सर्वेक्षकों की कमाई निर्भर करती हैथ कार्य की प्रकृति और असाइनमेंट पर। बीमा क्षेत्र में प्रवेश के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों की सूची। एक्चुरियल सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई एमिटी स्कूल ऑफ इंश्योरेंस एंड एक्चुरियल साइंस, नोएडा बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, मुंबई बीमा एवं जोखिम प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एक्चुरियल साइंसेज (आईएसएएस), हैदराबाद राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे उनमें से कुछ के नाम आईसीएफएआई स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, हैदराबाद हैं पूंजी बाजार में करियर उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था ने घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए पूंजी बाजार खोल दिया है। पूंजी बाजार में पूंजी के भारी प्रवाह, विशेष रूप से बड़े घरेलू खिलाड़ियों और (विदेशी संस्थागत निवेशकों) एफआईआई द्वारा और इसकी निरंतर वृद्धि ने इस क्षेत्र में रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा किए हैं। पूंजी बाजार में स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। म्यूचुअल फंड उद्योग आज पूंजी बाजार में सक्रिय भूमिका निभा रहा है और सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है। पूंजी बाजार में नौकरी वाणिज्य और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। हालाँकि किसी भी स्ट्रीम के इच्छुक उम्मीदवार कैपिटल मार्केट में अपना करियर बना सकते हैं। सेबी द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम अनिवार्य योग्यता वित्तीय बाजारों में एनएसई का प्रमाणन (एनसीएफएम) है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पास एनएसई के सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट्स (एनसीएफएम) - एक ऑनलाइन परीक्षण प्रणाली - अपनी तरह की एकमात्र लॉन्च करके परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड उत्पादों के विपणन और बिक्री में लगी किसी भी इकाई/व्यक्ति के लिए एएमएफआई प्रमाणन परीक्षण (सलाहकार मॉड्यूल) पास करना और एएमएफआई से पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रमाणीकरण परीक्षण की तारीख से 5 वर्षों तक वैध रहता है। एएमएफआई प्रमाणन वाले स्नातक म्यूचुअल फंड योजनाओं के विपणन और वितरण के लिए व्यवसाय विकास प्रबंधक/रिलेशनशिप प्रबंधक/सलाहकार के रूप में काम कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर/सलाहकार आदर्श निवेश पोर्टफोलियो की सिफारिश करके और ग्राहक संबंध बनाकर निवेशकों को उनकी वित्तीय योजना में सहायता करते हैं। इसी तरह, एनसीएफएम प्रमाणन वाले स्नातक स्टॉकब्रोकर के सहायक के रूप में काम कर सकते हैं या स्वतंत्र स्टॉकब्रोकर बन सकते हैं। स्नातक भी एजेंट/सलाहकार/वितरक बनना चुन सकते हैं और म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाएं बेच सकते हैं। इसके अलावा फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में वाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्त, गणित और प्रबंधन पृष्ठभूमि के उच्च योग्य पेशेवरों की आवश्यकता होती है जो फंड की अंतर्निहित प्रतिभूतियों (निवेशकों से निवेश के लिए प्राप्त धन) के निवेश के बारे में निर्णय लेते हैं, पूंजीगत लाभ या हानि का एहसास करते हैं, और लाभांश या ब्याज आय एकत्र करता है। पूंजी बाजार में चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए फाइनेंस, वित्तीय विश्लेषक, अर्थशास्त्र मास्टर और सांख्यिकी मास्टर के लिए भी नौकरी के व्यापक अवसर हैं। इसके अलावा पूंजी बाजार के कामकाज की गहरी जानकारी रखने वाले लोग कंसल्टेंसी को एक अच्छे विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। पूंजी बाजार में वेतनमान और अन्य पारिश्रमिक पूंजी बाजार युवा पीढ़ी के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है क्योंकि यह अत्यधिक लाभकारी है। शेयर बाजार दलालों और म्यूचुअल फंड एजेंटों की आय उनके द्वारा ग्राहकों को बेची गई योजनाओं की संख्या और प्रकार पर निर्भर करती है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि वे सालाना 2 लाख से 2.5 लाख रुपये आसानी से कमा सकते हैं. उच्च योग्य का पारिश्रमिकपेशेवर, जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उसकी प्रकृति पर और भी अधिक निर्भर होते हैं। सीए, एमबीए और सीएफए का अपेक्षित वेतन 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच हो सकता है। निजी वित्त योजनाकार/सलाहकार पूंजी बाजार में अपनी परामर्श सेवा से अच्छा रिटर्न अर्जित कर रहे हैं।

ज्ञान

एमबीबीएस में दाखिले का रास्ता है नीट यूजी परीक्षा

बारहवीं में बायोलॉजी लेने वाले अधिकतर छात्रों की योजना आगे चल कर डॉक्टर बनने की होती है। लेकिन इसमें वे छात्र ही सफल हो पाते हैं, जिनमें कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ने की इच्छाशक्ति होती है। आज देश के 600 से अधिक निजी व सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 92,000 से ज्यादा एमबीबीएस की सीटें हैं। वहीं हाल ही की खबर है कि भारत सरकार की ओर से मेडिकल में नई 75000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। तो, एमबीबीएस के कोर्स में दाखिले को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में यहां समझें :

n एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए प्रक्रिया : देश भर के तमाम सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET-UG) देना होगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा साल में एक बार आयोजित की जाती है।

n नीट यूजी के अंतर्गत 5.5 वर्षीय एमबीबीएस कोर्स में तो दाखिला होता ही है, वहीं 5 वर्षीय बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी), 5.5 वर्षीय बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी), 5.5 वर्षीय बीयूएमएस (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी) एवं 5.5 वर्षीय बीएचएमएस (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी) में भी दाखिले का आधार यही परीक्षा है।

n नीट यूजी प्रवेश परीक्षा की योग्यता क्या है : यदि आपने 12वीं की परीक्षा पीसीबी (फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो) विषयों के साथ उत्तीर्ण की है और आपकी अधिकतम आयु 25 वर्ष है, तो आप ये परीक्षा दे सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा की प्रक्रिया क्या है : परीक्षा शिड्यूल की घोषणा होगी, फिर एनटीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके बाद परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें रिजल्ट के आधार पर एक मेरिट सूची जारी की जाती है और उसके आधार पर आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग में आप अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का विवरण देते हैं, जिसके बाद आपके स्कोर को देखते हुए (मेरिट लिस्ट) आपको दाखिले के लिए सीट दी जाती है। भारत में केवल उस एमबीबीएस कोर्स के छात्र को डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए योग्यता प्रदान की गई है, जिस कोर्स की मान्यता भारत सरकार के अंतर्गत स्थापित नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी से है। इस संस्था को ही पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता था। स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई छात्र विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आता है और उसे भारत में एक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करना है, तो उसे भारत में फिर से इंटर्नशिप करनी होगी और फिर नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जिसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन नेशनल मेडिकल कमीशन में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर होगा।

दूसरे ग्रहों के जीवन पर नजर

आम इंसान ही नहीं, खुद वैज्ञानिक परग्रही सभ्यता (एलियंस) के बारे में जानने को इच्छुक रहे हैं। मगर इस मामले में शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाएं अभी कुछ भी ठोस रूप से कह नहीं पाती हैं। अनजान वस्तुओं (यूएफओ) और उड़न तश्तरियों के देखे जाने के हजारों दावे हैं। मगर कोई शीर्ष वैज्ञानिक इस पर कुछ कहने की कोशिश करता है, तो इस पर सनसनी ज्यादा पैदा होती है, ठोस कम हासिल होता है। इसकी वजह है कि इन वैज्ञानिकों के पास भी अपनी बात साबित करने के लिए ठोस साक्ष्यों का अभाव होता है। मगर अभी 'इसरो' प्रमुख ने सोशल मीडिया (यूट्यूब) पर यह धारणा व्यक्त की है कि इसकी बहुत संभावना है कि परग्रही सभ्यताएं हमारे मुकाबले में ज्यादा उन्नत हाँ और वे हमें देख रही हों या हम पर नजर रख रही हों। इसकी भी बहुत संभावना है कि पृथ्वी पर दूसरी दुनिया के प्राणी आते रहते हों। यह इस बात का सबूत है कि पृथ्वी के पा जीवन है। उन्होंने यह यह आशंका भी जताई कि पृथ्वी से अलग रासायनिक संरचना वाले जीवन से पृथ्वीवासियों को खतरा हो सकता है यानी एलियंस हम पर हमला कर सकते हैं।

हालांकि 'इसरो' प्रमुख ने भी अपने दावों के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। मगर जब वे यह कहते हैं कि परग्रही सभ्यताएं हमसे एक से दस हजार साल आगे हैं, तो उनके दावों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। उनके इस दावे का आधार यह है कि हम पृथ्वीवासी अभी अपने प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा से बाहर अपने कदमों की छाप नहीं छोड़ सके हैं। लेकिन 'एलियन' हमसे कई गुना ज्यादा उन्नत होने के कारण ब्रह्मांड में दूर तक आने-जाने की क्षमता रखते हैं। इन एलियंस से अगर हम इंसान कोई संपर्क या संवाद नहीं कर पा रहे हैं, तो यह कमी हमारी समझ, ज्ञान और नवाचार की है। क्योंकि इसकी अत्यधिक संभावना है कि एलियंस अपने तरीके से हमसे लगातार संपर्क और संवाद की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हम अपनी सीमाओं के कारण उनसे संवाद न कर पा रहे हों।

माना जाता है कि धरती पर रहने वाले मानव समुदाय का जब कभी परग्रही प्राणियों से पहली बार आमना-सामना होगा, तो इसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि हमें जीवन के उन रूपों का पता चलेगा, जो पृथ्वी की जैविक संरचनाओं से बिल्कुल अलग होंगे। यह भी हो सकता है कि तब हमें एलियंस कहलाने वाली परग्रही सभ्यताओं का कुल रवैया दोस्ती भरा लगे और जिस अनजान खतरे का अंदाजा सदियों से हम इंसान लगाते रहे हैं, वे सारे अनुमान एक झटके में उलट जाएं। पर ऐसा होने तक मानव सभ्यता एलियंस और अनजान आकाशीय वस्तुओं (यूएफओ) को अपने लिए खतरा मानती रह सकती है। इस कड़ी में एक चिंता कुछ महीने पहले जापान ने व्यक्त की थी। वहां सांसदों के एक बड़े समूह ने जून 2024 में उड़न तश्तरियों (अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग आब्जेक्ट यानी यूएफओ) को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। जापान के राजनीतिक नेतृत्व की चिंता है कि जिस तरह से दुनिया में ड्रोन तकनीक का इजाफा हुआ है, मुमकिन है कि ड्रोन की शक्ल में यूएफओ या यूएफओ की शक्ल में ड्रोन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नया खतरा पैदा कर दें। इसलिए जरूरी है कि यूएफओ कहलाने वाली वस्तुओं की गहन जांच की जाए और इनकी सत्यता का पता लगाया जाए।

कुछ समय पहले अमेरिका में भी यूएफओ और एलियंस को लेकर नए सिरे से काफी कुछ कहा-सुना गया। जैसे, बीते वर्ष 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' ने कहा था कि वह यूएफओ और एलियंस संबंधी घटनाओं से जुड़ी चर्चाओं को सनसनी से अलग कर- के देखने और उन्हें विज्ञान के तराजू पर तौलने की हिमायती है। अमेरिकी सरकार ने इन्हीं पहलकदमियों के बीच उड़न तश्तरियों की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया था। समिति के सामने यूएफओ देखे जाने की 510 घटनाओं का ब्योरा जांच के लिए रखा गया है, जिनमें से ज्यादातर को आकाश में उड़ने वाले बड़े गुब्बारों से जोड़ा जाता है। इन गुब्बारों को पड़ोसी मुल्कों के जासूसी उपकरण माना जाता है। इन गुब्बारों में जासूसी वाला कोण हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यूएफओ से जुड़ने वाली हर घटना के पीछे कोई जासूसी संबंधी मामला हो।

परग्रही सभ्यता के अस्तित्व में भरोसा रखने वालों के नजरिए से देखें तो कहा जा सकता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। इसलिए यह सोचना सांख्यिकीय तर्क के हिसाब से सही हो सकता है कि उनमें कहीं न कहीं जीवन हो। हालांकि पिछले कई दशक से दुनिया भर के वैज्ञानिकों इससे जुड़े रहस्यों का जो जवाब खोजा था, वह यही है कि ब्रह्मांड में इंसान अकेला है। मगर इस उत्तर को मुकम्मल न मानने की एक वजह यह है कि दूसरी दुनिया की खोज के काम में ब्रह्मांडीय दूरियों के अलावा तकनीकी सीमाएं रही हैं। दुनिया के पास न तो बेहद ताकतवर टेलीस्कोप थे और न ही वैसे सिग्नल पकड़ने वाले यंत्र, जो अंतरिक्ष से आने वाली हर सूक्ष्म आहट को एक अलग प्रकार के जीवन की तरफ से संवाद की कोशिश के रूप में दर्ज कर सकें। दूसरी बड़ी खामी इस मान्यता में जकड़े रहने की रही है कि दूसरी दुनिया भी हमारी पृथ्वी जैसी होगी और उस पर इंसान जैसे जीव ही बसते होंगे। 'नासा' ने कहा है कि अब वह आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यूएपी यानी 'अनआइडेंटिफाइड एनोमेलस फेनोमेना' की जांच करेगी। नासा के मुताबिक इससे यह साफ हो सकेगा कि जो चीजें हमारे सौरमंडल से गुजर कर पृथ्वी तक आई हैं, उनके पीछे असल में कौन है।

ऐसा क्यों है कि परग्रही सभ्यता और यूएफओ के बारे में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। इसका एक समझदार जवाब वर्ष 2016 6 में। शोध जर्नल 'एस्ट्रोबायोलाजी' में प्रकाशित हुआ था। इसमें अंतरिक्ष विज्ञानी आदित्य चोपड़ा और चार्ली लाइनवीवर ने यह निष्कर्ष दिया था कि पृथ्वी से परे अन्य ग्रहों पर जीवन के लायक हालात ही नहीं हैं। लिहाजा, उन पर एलियंस (समझदार परग्रही प्राणी) तो क्या, कैसा भी जीवन संभव नहीं है। यहां तक कि सौरमंडल के ही ग्रह मंगल और शुक्र पर 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन लायक स्थितियां बनी थीं, पर वहां भी पर्यावरण इतना अनुकूल नहीं रहा कि एलियंस पैदा हो पाएं। मगर हमारा इंटरनेट सौरमंडल को पार कर पृथ्वी तक आने वाली उड़न तश्तरियों या अजीबोगरीब किस्म के यानों की जिन वीडियो फुटेज से भरा पड़ा है। उसके बारे में दावा किया जाता है कि तकनीकी खामियों के कारण यह समस्या हमारी है कि हम अरबों-खरबों प्रकाशवर्ष दूर से आने वाले इन संकेतों को पकड़ और समझ नहीं पा रहे हैं।

-विजय गर्ग

आंसुओं का सौंदर्य

विजय गर्ग

हंसने वाले को कोई अधिक समय तक हंसने से न रोके, रोने वाले को कोई अधिक समय तक रोने से न रोके। और कोई अधिक समय तक सोने वाले को न जगाए या जगाने वाले को कोई सोने को न बोले, तब की दुनिया कुछ और होगी। दरअसल, यह हंसना और रोना हमारी जिंदगी का फलसफा है। प्रकृति की ऐसी नियामत है, जिसके कारण ही मनुष्य मनुष्य होता है। यह रोना ही है, जो एक तरह से हमारे जीवन की बोहनी है यानी आगाज जब हम दुनिया में कदम रखते हैं तो रोते हुए आते हैं। फिर अगर हम रोते हैं तो परिजन खुश होते हैं और अगर नवजात शिशु का रुदन न सुनाई पड़े तो परिजन चिंतित हो जाते हैं और उसे किसी भी तरह रुलाया जाता है। समझने की बात यह है कि अगर हमारी आमद ही रोने से हुई है, तो जीवन में इसका स्थान कैसे बेशकीमती नहीं होगा ! हम चाहें या न चाहें, रोना और आंसू हमारी नियति है, हमारी प्रकृति का अनिवार्य हिस्सा है। इससे हम चाहें जितना भी बचना चाहें, बच नहीं सकते और इसीलिए जो स्थितप्रज्ञ मनीषी होते हैं, वे इससे ऊपर उठ जाते हैं और जिंदगी का असल आनंद लेते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में माया भी कहा गया है जो जीवन का परम सत्य है। इससे भला कौन बच सकता है ! जहां तक बात है रोने की, तो इसमें मनुष्यता का सौंदर्य छिपा हुआ है। जब मनुष्य नैसर्गिक रूप बहाता है तो उसे सुकून मिलता है। यह रोना ही है, जो मनुष्य को मनुष्य बना देता है और अन्य प्राणियों से थोड़ा अलग कर देता है। यह हमारे आंसू ही हैं जो हमारी संवेदना की पहचान हैं। हम जब कोई दर्द भरी कहानी पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर मोपासां का उपन्यास 'एक महिला की जिंदगी' में कुछ ऐसा

आंसू अंकन देखते हैं, तो हमारे आंसू बहने लगते हैं। सच्चाई यह है कि जिंदगी में हमारे परिवार में आसपास दुख ही दुख है, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और उसमें हमें खुशियां ढूंढ़नी पड़ती हैं। जब हम खुश होते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जब ज्यादा मुस्कराते हैं, ज्यादा खुश होते हैं तो हम हंसने लगते हैं। इसका भी जिंदगी में अत्यंत महत्त्व है। शायद इसी वजह से कहा गया है कि दुख भरी जिंदगी की नदी में हंसना या हंसी कुछ ऐसे है, जैसे अंधेरे में सितारों का टिमटिमाना।

इस तरह हमारी जिंदगी होने और हंसने के बीच एक ऐसा पेंडुलम है, जहां रास्ता सकारात्मकता ढूंढ़ता है। साफ-साफ कहा जाए, तो यह आंसू ही है जो हमारी जिंदगी का आगाज है और अंत भी। जब प्राणी देह त्याग करता है तो खुद भी पीड़ा में दुखी होता है और उसकी मृत्यु के बाद सारा परिवार और चाहने वाले आंसू बहाते हैं। बहुत कम ऐसे पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष होते हैं, जो

अपनी मौत को दुनिया के लिए एक पैगाम बना देते हैं, जिससे समाज और दुनिया एक संदेश ग्रहण करती है। सोचने की बात यह है कि यह प्रकृति का कैसा खेल है कि जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो वह रोते हुए दुनिया में आता है। जितना सहज आंसू बहाना, रोना है, उससे बहुत बहुत ज्यादा कठिन है हंसना। यही कारण है कि खुशी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसकी कोई तुलना नहीं है। मगर यह रोना या आंसू बहाना भी कोई हंसी खेल नहीं है। ईमानदार आंसू वही बहा सकता है जो सच्चे अर्थों में मनुष्य है, क्योंकि इसके पीछे है पाक-साफ हृदय का प्रति-स्थापित होना। आंखों में आंसू सहज रूप से उन्हीं के आते हैं, जो संवेदनशील होते हैं, जो पूर्ण रूप से मनुष्य होते हैं। इसलिए आंसुओं का जिंदगी में बहुत महत्त्व है और इसे सहेज कर रखने को कहा जाता है।

अगर हम गीत, कविता की बात करें, कहानी की बात करें, तो विभिन्न कलाओं में आंसू और खुशियां समाहित हैं और इन्हें महसूस करके मनुष्य और ज्यादा मनुष्य बनता है। अगर हम यह कल्पना करें कि जिंदगी में आंसू न हो, रोना न हो या फिर हंसना न हो तो फिर जिंदगी कैसी होगी, इसकी कल्पना करने से ही समझ सकते हैं कि वह जिंदगी सिर्फ एक रोबोट सदृश बनकर रह जाएगी। बल्कि अब तो रोबोट को भी कृत्रिम संवेदनात्मक अभिव्यक्तियों से लैस बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमें अपने आंसू छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह हम अपनी खुशी, अपनी हंसी प्रदर्शित करते हैं, हमें अपने आंसू नहीं छिपाना चाहिए और छिपाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अगर हमारे पास है, तो यह हमारी धरोहर है।

जाने कितने किस्से और कितनी कहानियां हैं या कहा जाए कि शायद बहुत कम ऐसा सृजन होगा, जिनमें ऐसे दृश्य अनिवार्य रूप से हैं, जिन्हें पढ़ कर आदमी की आंखें नम नहीं हो जाती हैं या फिर होठों पर हंसी न आ जाती हो। एक कवि के सृजन का यह मान ही है कि कोई उसकी रचना को पढ़कर आह उच्चारित करे और दुखी हो जाए। यह स्थिति उस साहित्य के उच्चतर होने का प्रतीक है। इसी तरह, अगर हमें कोई हंसाता है, तो उसका मान- समाज में बढ़ जाता है, क्योंकि हंसना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दरअसल, हमें जगाने वाले और सुलाने वाले, हंसाने वाले और आंसू पोंछने वाले जो लोग होते हैं, वही हमारे असल शुभचिंतक होते हैं, चाहे वह कोई अपना हो या फिर पराया।

कंपनियां क्यों लाती हैं IPO, पैसे लगाने से पहले किन बातों का रखना चाहिए ध्यान?

परिवहन विशेष न्यूज

शेयर मार्केट में इस वक्त आईपीओ की बहार आई है। बहुत-सी कंपनियां अपना आईपीओ ला चुकी हैं और कई लाने की तैयारी में हैं। निवेशक भी आईपीओ को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ज्यादातर में अच्छा-खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है। हालांकि आईपीओ में पैसे लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आईपीओ क्या होता है इसे कंपनियां क्यों लाती हैं।

नई दिल्ली। शेयर मार्केट में निवेश करने के कई तरीके हैं। इनमें से आईपीओ यानी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग। कई बार आईपीओ काफी कम समय में काफी अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ ने निवेशकों को 114 फीसदी का लिस्टिंग गेन दिया। हालांकि, आईपीओ में निवेश करने और उससे अच्छा रिटर्न पाने के लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा। मसलन, आईपीओ क्या होता है, इसे कंपनियां क्यों लाती हैं और इसमें निवेश करने से क्या होता है।

IPO क्या होता है और कंपनी इसे क्यों लाती है?

जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, तो वह अपना आईपीओ (What is IPO) लाती है। इसकी कुछ वजहें होती हैं। कई बार कंपनी को अपना कर्ज घटाने, कामकाज जारी रखने या फिर कारोबार का विस्तार करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। चूंकि, कोई भी कंपनी बैंकों से तय मात्रा में ही कर्ज ले सकती है, तो वह आईपीओ लाकर जनता से पैसे जुटाती है। इसमें कंपनी अपने शेयर बेचती है और उससे मिलने वाले पैसों को कारोबार बढ़ाने पर खर्च करती है।

आईपीओ में निवेश करने से क्या फायदा होता है?

आईपीओ में निवेश करने से आपको कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हो जाते हैं। आईपीओ के लिस्ट होने के बाद आपको अच्छा लिस्टिंग गेन (IPO Investment Benefits) मिल सकता है, जैसा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस और कई अन्य आईपीओ के मामले में हुआ है। अगर लिस्टिंग के बाद भी शेयर बढ़ता है, तो भी आपको मुनाफा (IPO Profits) हो सकता है। आप लिस्टिंग के बाद भी शेयर को खरीद-बेच सकते हैं। साथ ही, अगर कंपनी मुनाफे के स्थिति में डिविडेंड बांटती है, तो आपको उसका भी लाभ मिलेगा।

क्या आईपीओ में निवेश करने में जोखिम भी हैं?

इसका सीधा और सरल जवाब है, हां। आप अक्सर सुनते होंगे कि शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और आईपीओ भी इसका अपवाद नहीं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस से निवेशकों को तगड़ा मुनाफा हुआ। लेकिन, फिनटेक कंपनी पेटीएम जैसे आईपीओ भी हैं, जिसके आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों को भारी नुकसान (IPO Investment Risk) हुआ। पेटीएम ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 2,080 से 2,150 रुपये प्रति शेयर रखा था। लेकिन, यह लिस्टिंग के दिन ही घटकर 1,586.25 रुपये पर आ गया।

IPO में आप किस तरह से निवेश कर सकते हैं?

आईपीओ में निवेश करने के लिए डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी ब्रोकरेज में ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए आधार और पैन कार्ड जैसे कुछ डॉक्युमेंट लगते हैं। साथ ही, बैंक डिटेल भी जरूरी होती है। फिर भी आप किसी भी आने वाले आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। आप जैसे ही आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे कि आपके अकाउंट में उतनी रकम फ्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कि आपके अकाउंट से पैसे तभी कटेंगे, जब आपको शेयर अलॉट जाएगा। नहीं तो आपके पैसे एक दिन वापस मिल जाएंगे।

आईपीओ में प्राइस बैंड और लॉट साइज क्या होता है?

प्राइस बैंड और लॉट साइज आईपीओ के सबसे अहम हिस्से होते हैं। कोई भी आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 3-5 दिन तक खुला रहता है। कंपनी एक प्राइस बैंड तय करती है और आप उसी के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। हालांकि, इसमें आप सेकेंडरी मार्केट की तरह 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते। आपको पूरा लॉट खरीदना होता है। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ का प्राइस बैंड 66 से 70 रुपये था। आईपीओ का लॉट साइज 214 शेयरों का था। इसका मतलब कि निवेशक को कम से कम 214 शेयर खरीदने होंगे।

आईपीओ में निवेश के दौरान सतर्कता भी जरूरी

IPO में शेयरों की बिक्री दो तरह से होती है। एक तो कंपनी फ्रेश इक्विटी जारी करती है। इस तरह के आईपीओ को अच्छा समझा जाता है, क्योंकि इसमें मिलने वाली पूंजी कंपनी का कारोबार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। वहीं, कुछ आईपीओ में मौजूदा शेयरहोल्डर्स अपनी

हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलते हैं, जिसे ऑफर फॉर सेल (OFS) कहते हैं। अगर कोई आईपीओ सिर्फ ऑफर फॉर सेल वाला है, तो उससे विशेष सजग रहने की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें कंपनी कोई पैसा नहीं मिलता।

आईपीओ की कम या अधिक डिमांड पर क्या होता है?

अगर कोई कंपनी IPO लाती है और उसे निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो वह अपना IPO वापस ले सकती है। हालांकि, कंपनी के कितने फीसदी शेयर की बिकने चाहिए, इसे बारे में कोई खास नियम नहीं है। वहीं, अगर आईपीओ की अधिक डिमांड रहती है, तो सेबी के तय फॉर्मूले के मुताबिक शेयरों का अलॉटमेंट होता है। इसमें कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के जरिए तय किया जाता है कि किस निवेशक को शेयर मिलेगा और किसे नहीं। जैसे कि किसी निवेशक ने 5 लॉट के लिए अप्लाई किया है, तो उसे 1 या 2 लॉट भी मिल सकते है। हो सकता है कि किसी निवेशक को एक भी लॉट न मिले।

क्या 75 फीसदी लोग बंद कर देंगे UPI का इस्तेमाल? सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा

परिवहन विशेष न्यूज

देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface -UPI) का चलन तेजी से बढ़ा है। ज्यादातर लोग छोटे-बड़े ट्रांजैक्शन के लिए UPI ऐप यूज कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी है यूपीआई का सुविधाजनक होने के साथ मुफ्त होना। फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार इस पर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है।

नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेस (UPI) ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया ही बदलकर रख दी। आज पान की दुकान से लेकर सब्जी के ठेले तक QR कोड स्कैनर लगे नजर आ जाते हैं, जिसकी मदद से आप चुटकियों में पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई अब हर 10 में से 4 लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। ऐसे में यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि यूपीआई के बगैर पेमेंट की दुनिया कैसी होगी।

इसके बावजूद 75 फीसदी लोग यूपीआई का इस्तेमाल बंद करने का इरादा रखते हैं। दरअसल, इस तरह की खबरें आई थी कि सरकार यूपीआई से लेनदेन पर टांजैक्शन फीस लगा सकती है। इस पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी चर्चा हुई। हालांकि, काउंसिल ने अगली मीटिंग के लिए इस पर फैसला टाल दिया दिया।

यूपीआई का यूज बंद करेंगे लोग?

लोकलसर्किल्स (LocalCircles) के एक सर्वे में यूपीआई के बारे में कई दिलचस्प बातें निकलकर सामने आईं। सर्वे के मुताबिक, अगर यूपीआई के लेनदेन पर कोई शुल्क लगाया जाता है, तो तकरीबन 75 फीसदी यूजर्स इसका इस्तेमाल बंद करेंगे। सर्वे से यह भी पता चला कि 38 फीसदी लोग यूपीआई पर काफी ज्यादा निर्भर हैं। वे अपने टोटल ट्रांजैक्शन में से 50 फीसदी से अधिक यूपीआई के जरिए ही करते हैं। बाकी में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य डिजिटल माध्यम हैं।

यूपीआई 10 में से लगभग 4 यूजर्स के पेमेंट लाइफ का अभिन्न हिस्सा बन रहा है। वे यूपीआई पर किसी तरह के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लेनदेन शुल्क लगाए जाने के पक्ष में नहीं हैं। हम अपने सर्वे के निष्कर्षों को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास भेजेंगे, ताकि किसी भी एमडीआर शुल्क की अनुमति देने से पहले यूपीआई यूजर्स की नब्ज को ध्यान में रखा जा सके।

लोकलसर्किल्स, सर्वे एजेंसी

सर्वे में कितने लोग शामिल हुए

लोकलसर्किल्स के सर्वे में तीन व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। सर्वे एजेंसी के दावे के मुताबिक, 308 जिलों से 42,000 उत्तर प्राप्त हुए हैं। सर्वे में कहा गया है, ₹सर्वे में शामिल UPI यूजर्स में से सिर्फ 22 प्रतिशत भुगतान पर लेनदेन शुल्क का बोझ उठाने को तैयार हैं। वहीं, 75 प्रतिशत ने कहा कि अगर लेनदेन शुल्क लगाया जाता है, तो वे UPI का उपयोग करना बंद कर देंगे। UPI लेनदेन शुल्क से जुड़े सवालों पर 15,598 उत्तर प्राप्त हुए।

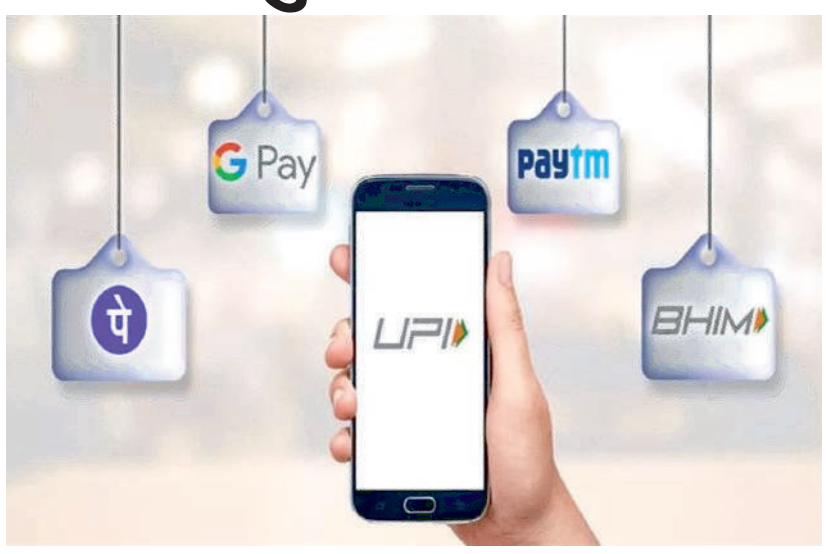

EPFO से 20 लाख नए सदस्य जुड़े, श्रम मंत्री बोले- बढ़ रहे रोजगार के मौके

जुलाई में लगभग 3.05 लाख नई महिला सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुईं जो साल-दर-साल 10.94 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। कुल मिलाकर 4.41 लाख शुद्ध महिला सदस्य जोड़ी गईं जो पेरोल ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से एक महीने में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या को दर्शाता है। जुलाई 2023 की तुलना में महिला सदस्यों में 14.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जुलाई में 19.94 लाख सदस्य जोड़े। यह अप्रैल, 2018 में पेरोल डाटा शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा मासिक संख्या है। जहां तक शुद्ध रूप से नए सदस्यों की बात है तो इनकी संख्या 10.52 लाख है, जो जून की तुलना में 2.66 प्रतिशत और पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.43 प्रतिशत अधिक है।

श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नई सदस्यता में उछाल का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के सफल आउटरीच कार्यक्रमों को दिया जा सकता है।

ईपीएफओ से बाहर निकलने वाले लगभग 14.65 लाख सदस्य जुलाई में फिर से संगठन से जुड़े। यह आंकड़ा साल-दर-साल 15.25 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। जुलाई में जुड़े 8.77 लाख सदस्य 18-25 वर्ष आयु वर्ग के हैं। 18-25 वर्ष की आयु के लगभग 6.25 लाख लोग पहली बार काम कर रहे हैं या नए सदस्य हैं। करीब 59.4 प्रतिशत नए सदस्य 18-25 वर्ष आयु वर्ग के हैं।

जुलाई में लगभग 3.05 लाख नई महिला सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुईं, जो साल-दर-साल 10.94 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। कुल मिलाकर, 4.41 लाख शुद्ध महिला सदस्य जोड़ी गईं, जो पेरोल ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से एक महीने में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या को दर्शाता है। जुलाई 2023 की तुलना में महिला सदस्यों में 14.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्रम मंत्रालय के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात की हिस्सेदारी कुल सदस्यों में 59.27 प्रतिशत है। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा सदस्य जुड़े और कुल जुड़े नए सदस्यों में इसका योगदान 20.21 प्रतिशत रहा।

डेटा के अनुसार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा और गुजरात में कुल शुद्ध सदस्य जोड़ का 59.27 प्रतिशत हिस्सा है। महाराष्ट्र राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे रहा, जिसने कुल नए सदस्यों में 20.21 प्रतिशत का योगदान दिया।

F&O के चक्रव्यूह में 93 फीसदी लोग गंवा रहे पैसा, फिर भी क्यों नहीं छूट रही 'लत'

नई दिल्ली। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेडिंग में पैसा गंवाने वाले निवेशकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मार्केट रेगुलेटर- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले तीन साल में 93 फीसदी ट्रेडर्स ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 1.8 लाख करोड़ रुपये लुटा दिए। पिछले साल भी सेबी ने ऐसी ही एक रिपोर्ट जारी की थी, तब पता चला था कि वित्त वर्ष 2022 में 89 फीसदी इंडिविजुअल ने इक्विटी F&O ट्रेडिंग में पैसे गंवाए थे।

औसत घाटा 2 लाख रुपये का

सेबी की हालिया स्टडी बताती है कि 1 करोड़ से अधिक इंडिविजुअल एफएंडओ सेगमेंट में ट्रेडिंग करते हैं। इनमें से 93 फीसदी तीन वित्त वर्षों में नुकसान में रहे। उनका औसत घाटा करीब 2 लाख रुपये रहा। इसनमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है। इन 93 फीसदी में साढ़े तीन फीसदी यानी करीब 4 लाख ऐसे ट्रेडर्स हैं, जिनका औसत घाटा 28 लाख रुपये रहा। अगर मुनाफे की बात करें, तो सिर्फ 1 फीसदी ट्रेडर्स ही 1 लाख रुपये से अधिक का प्रॉफिट कमाने में सफल रहे।

लगातार घाटे के बावजूद ट्रेडिंग

F&O ट्रेडिंग में नुकसान उठाने वाले अधिकतर ट्रेडर्स कम आय वाले हैं। सेबी की स्टडी बताती है कि F&O ट्रेडिंग में करीब 75 फीसदी इंडिविजुअल ऐसे थे, जिनकी इनकम वित्त वर्ष 2023-24 में 5 लाख रुपये कम थी। साथ ही, 75 ट्रेडर्स लगातार घाटे के बावजूद F&O ट्रेडिंग जारी रखे हुए हैं। अगर उम्र के लिहाज से देखें, तो F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग करने वाले 30 साल से कम उम्र के नौजवानों की संख्या वित्त वर्ष 2023 में 31 फीसदी से उछलकर वित्त वर्ष 2024 में 43 फीसदी पर पहुंच गई।

दूसरी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपेंट एजेंसी बन सकती है यह कंपनी, जल्द आने वाला है आईपीओ

परिवहन विशेष न्यूज

एनटीपीसी (NTPC) की सब्सिडियरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ का साइज 10000 करोड़ रुपये हो सकता है। इसकी पैरेंट कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड का शेयर (NTPC Share) पिछले पांच साल में अपने शेयरहोल्डर्स का पैसा तीन गुना कर चुका है। कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) सेबी के पास जमा कराया गया है। आइए जानते हैं इस आईपीओ की पूरी डिटेल।

नई दिल्ली। बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी की सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) नवंबर के पहले हफ्ते में आ सकता है। कंपनी ने पिछले सप्ताह ही 10 हजार करोड़ रुपये जुटाने के लिए सेबी के प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए हैं।

सूत्रों ने बताया कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी देश-विदेश में रोडशो करने की भी योजना बना रही है। यह पूरा आईपीओ नए शेयरों पर आधारित होगा और इसमें प्रमोटरों के शेयर बिक्री के लिए पेश नहीं किए जाएंगे। दूसरी ओर, सेबी ने सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी वारे एनर्जीज और डिजिटल पेमेंट्स सेवा प्रदाता वन मोबीक्विक सिस्टम्स को आइपीओ की मंजूरी दे दी है।

लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देंगे भारतीय बाजार

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले निवेशकों को भारतीय बाजार बेहतर रिटर्न देंगे। रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय शेयर बाजार पांच वर्ष और दस वर्ष की निवेश अवधि के लिए आकर्षक बने रहेंगे।

रिपोर्ट में भारतीय बाजारों के उच्च मूल्यांकन, और पूंजीगत लाभ कर में की गई वृद्धि की ओर इशारा किया गया है, लेकिन भारतीय बाजारों के लचीलेपन पर भी ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इन चुनौतियों का सामना करने की बाजार की क्षमता ने मजबूत दीर्घकालिक दृष्टिकोण और निवेशकों के विश्वास को प्रदर्शित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अभी भी शेयर संस्कृति के निर्माण के शुरुआती दौर में है।

प्याज के बढ़ते भाव से सरकार परेशान, कीमतों को काबू में रखने के लिए उठाया खास कदम

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 22 सितंबर को दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 55 रुपये प्रति किलोग्राम थी जो एक साल पहले की समान अवधि में 38 रुपये प्रति किलोग्राम थी। मुंबई तथा चेन्नई में कीमतें क्रमश 58 रुपये और 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। सरकार समूचे भारत में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री बढ़ाने की योजना बना रही है।

नई दिल्ली। सरकार ने हाल ही में निर्यात शुल्क हटाए जाने के बाद खुदरा कीमतों में आए उछाल के मद्देनजर थोक बाजारों में 'बफर स्टाक' से बिक्री बढ़ाकर प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने की कोशिश तेज कर दी है। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के थोक बाजारों में अपने 'बफर स्टाक' (भंडार) से प्याज निकालना शुरू कर दिया है। सरकार की योजना पूरे देश में सब्सिडी वाले प्याज की खुदरा बिक्री की है। सरकार ने 10 दिन पहले प्याज पर 550 डालर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया था।

खरे ने कहा, 'निर्यात शुल्क हटाने के बाद हमें कीमतों में उछाल का अनुमान था। 4.7 लाख टन के 'बफर स्टाक' और खरीफ की बुआई के बढ़े हुए रकबे के साथ हमें उम्मीद है कि प्याज की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी।' सरकार समूचे भारत में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री बढ़ाने की योजना बना रही है। इनमें उन शहरों पर ध्यान अधिक दिया जा रहा है जहां कीमतें राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 22 सितंबर को दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 55 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो एक साल पहले की समान अवधि में 38 रुपये प्रति किलोग्राम थी। मुंबई तथा चेन्नई में कीमतें क्रमशः 58 रुपये और 60 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं। सरकार दिल्ली और अन्य राज्यों की राजधानियों में मोबाइल वैन और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) तथा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) की दुकानों के जरिये पांच सितंबर से 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेच रही है।

आयात शुल्क वृद्धि के बाद खाद्य तेलों के दाम बढ़े

खाद्य तेलों के संबंध में उन्होंने हाल ही में आयात शुल्क वृद्धि के बाद कीमतों में बढ़ोतरी की बात को स्वीकार किया और बताया कि यह कदम घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत और प्रोसेस्ड सूरजमुखी तेल पर 32.5 प्रतिशत कर दिया था जिसका उद्देश्य घरेलू तिलहन किसानों और प्रसंस्करणकर्ताओं को समर्थन देना था।

टमाटर के बारे में खरे ने कहा कि सरकार रुझानों पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेगी। घरेलू अरहर और उड़द उत्पादन के अच्छे रहने और दालों के आयात में वृद्धि के साथ खरे को आने वाले महीनों में दलहन कीमतों में स्थिरता की उम्मीद है।

अनिल अंबानी की इस कंपनी की नहीं थम रही रफ्तार, लगातार चौथे दिन लगा अपर सर्किट

अनिल अंबानी के ग्रुप की रिलायंस पावर के शेयरों में लगातार चौथे कारोबारी दिन अपर सर्किट लगा है। विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के लिए गारंटर के तौर पर 3872 करोड़ रुपये के पूरी देनदारी चुका दी है। रिलायंस पावर के मुताबिक अब उस पर बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई बकाया नहीं है। इससे निवेशक रिलायंस पावर के शेयरों पर टूट पड़े हैं।

नई दिल्ली। एशिया के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयरों में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। यह लगातार चौथा दिन है, जब रिलायंस पावर के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। अपर सर्किट का मतलब होता है कि बहुत-से लोग शेयर खरीदना चाहते हैं, लेकिन बेचने वाला कोई नहीं।

सोमवार को 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ रिलायंस पावर का शेयर 38.16 रुपये पर पहुंच गया। यह इसका 52 हफ्तों यानी एक साल का उच्चतम स्तर भी है।

रिलायंस पावर के शेयरों में तेजी क्यों

आज यानी 23 सितंबर को रिलायंस पावर के बोर्ड की मीटिंग होने वाली है। इसमें फंड जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अनिल अंबानी की पावर कंपनी घरेलू बाजार के साथ ही ग्लोबल मार्केट से भी पैसा जुटाना चाहती है। अनिल अंबानी की दो कंपनियों ने हाल ही में अपना कर्ज कम किया है और इससे उनके शेयरों में जोरदार उछाल देखा जा रहा है। इनमें रिलायंस पावर के साथ रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का नाम भी शामिल है।

रिलायंस पावर के आ रहे अच्छे दिन

अनिल अंबानी की रिलायंस पावर ने इससे पहले बुधवार को बताया था कि उसने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के लिए गारंटर के तौर पर 3,872 करोड़ रुपये की पूरी देनदारी चुका दी है। यह रिलायंस पावर की सब्सिडियरी कंपनी थी। विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर के पास नागपुर के बुटीबोरी में 600 मेगावाट का पावर प्लांट है। इस यह प्लांट मुंबई को बिजली सप्लाई में अहम भूमिका निभाता है। इस प्लांट को अदाणी ग्रुप खरीदना चाहता है। अब रिलायंस पावर के कर्ज चुकाने से इस डील की राह आसान हो गई है।

POSH कानून और इसके कानूनी परिणाम

महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के मामलों में रोकथाम, शिकायत और निवारण के लिए 'POSH' (Prevention of Sexual Harassment) कानून 2013 में लागू किया गया। यह कानून महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जहाँ वे बिना किसी भय के काम कर सकें।

POSH कानून के तहत, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है, जिसमें अशोभनीय टिप्पणी, शारीरिक संपर्क, अश्लील सामग्री दिखाना या किसी भी प्रकार की यौनिक इच्छा से प्रेरित व्यवहार शामिल है। यह कानून न केवल संगठनों के लिए बाध्यकारी है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हर कर्मचारी, विशेष रूप से महिलाएं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक हों।

POSH कानून के तहत प्रमुख प्रावधान:

आंतरिक शिकायत समिति (ICC): हर कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। यह समिति यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करती है।

समय-सीमा: शिकायत दर्ज होने के 90 दिनों के भीतर जांच पूरी की जानी चाहिए, और जांच समिति को 60 दिनों के भीतर निष्कर्ष निकालना होता है।

संवेदनशीलता प्रशिक्षण: सभी कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न से संबंधित जागरूकता और प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है, ताकि वे अपने अधिकारों और दायित्वों के बारे में जान सकें।

गोपनीयता: POSH के तहत शिकायतकर्ता की पहचान और शिकायत से संबंधित सभी जानकारी गोपनीय रखी जाती है, जिससे पीड़िता को किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

विशेष साक्षात्कार: डॉ. अंकुर शरण (External ICC Member) - POSH कानून के प्रति जागरूकता और समाज में बदलाव के अग्रदूत

साक्षात्कारकर्ता: आज हमारे साथ हैं डॉ. अंकुर शरण, एक सफल Logistician और External ICC Member के रूप में कार्यरत, जिन्होंने POSH कानून के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही, उन्होंने एक Socialpreneur के रूप में कई जागरूकता अभियानों की शुरुआत की है। आइए जानते हैं उनसे उनके अनुभव और सुझाव।

सवाल: डॉ. शरण, External ICC Member के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा है?

डॉ. अंकुर शरण: एक External ICC Member के रूप में काम करने का अनुभव काफी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा रहा है। इस भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करना सुनिश्चित किया जाए। कई बार महिलाएं डर, संकोच या प्रतिशोध के डर से शिकायत करने से पीछे हटती हैं, लेकिन हमारी समिति का काम है कि उन्हें आत्मविश्वास दिया जाए और निष्पक्ष तरीके से उनके मामलों की जांच की जाए।

सवाल: POSH कानून के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आपने क्या पहल की हैं?

डॉ. अंकुर शरण: जागरूकता फैलाने के लिए हमने कई मेगा जागरूकता अभियानों की शुरुआत की है। मेरा मानना है कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी कर्मचारियों को उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। हमने कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न कार्यस्थलों पर संवेदनशीलता प्रशिक्षण और विचार गोष्ठियों का आयोजन किया है, जहाँ हम यौन उत्पीड़न को कैसे पहचाना जाए और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा करते हैं।

सवाल: आपको किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और आपने उनका समाधान कैसे किया?

डॉ. अंकुर शरण: सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक मानसिकता को बदलने की है। कई बार लोग यौन उत्पीड़न को हल्के में लेते हैं या इसे केवल महिलाओं का मुद्दा मानते हैं। इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए हमने पुरुषों को भी जागरूक करने पर जोर दिया है, क्योंकि यह एक सामाजिक मुद्दा है, न कि केवल महिला या पुरुष का। दूसरी चुनौती यह थी कि शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा और गोपनीयता कैसे प्रदान की जाए। इसके लिए हमने ICC की प्रक्रियाओं में सख्त गोपनीयता नीतियाँ लागू की हैं।

सवाल: आपके अनुसार POSH कानून के लागू होने के बाद कार्यस्थल पर किस तरह का बदलाव देखा गया है?

डॉ. अंकुर शरण: POSH कानून लागू होने के बाद कार्यस्थलों पर निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव हुए हैं। अब अधिकांश कंपनियाँ इस कानून का सख्ती से पालन कर रही हैं। जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण सत्रों के कारण, महिलाएँ अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो गई हैं। साथ ही, पुरुष कर्मचारी भी अब अधिक जिम्मेदार और संवेदनशील हो गए हैं। कंपनियाँ अब ICC का गठन कर रही हैं और पीड़ितों को सुनने और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ कर रही हैं।

सवाल: एक Socialpreneur के रूप में आपका उद्देश्य क्या है?

डॉ. अंकुर शरण: मेरा उद्देश्य सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को एक सुरक्षित और समावेशी स्थान बनाना है। इसके लिए मैंने सामाजिक उद्यमिता का सहारा लिया है। मैं उन क्षेत्रों में भी जागरूकता फैलाने का प्रयास करता हूँ जहाँ POSH कानून और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी सीमित है। इसके तहत मैं कई गैर-सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ काम कर रहा हूँ, ताकि समाज के सभी वर्गों तक यह संदेश पहुँच सके।

सवाल: आपकी भविष्य की योजनाएँ क्या हैं?

डॉ. अंकुर शरण: मेरी योजना है कि जागरूकता अभियानों को और बड़े स्तर पर पहुँचाया जाए। हम तकनीकी और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके POSH कानून के बारे में और अधिक जानकारी फैलाने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा, मैं विभिन्न CSR (Corporate Social Responsibility) प्रोग्राम्स के तहत कंपनियों के साथ साझेदारी करके इस मुद्दे पर अधिक काम करने की योजना बना रहा हूँ, ताकि कार्यस्थल और समाज में हर किसी को सुरक्षित माहौल मिल सके।

सवाल: अंत में, हमारे पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

डॉ. अंकुर शरण: मेरा सभी से यही कहना है कि POSH कानून सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ हर व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएँ, बिना किसी भय या असुरक्षा के काम कर सकें।

साक्षात्कारकर्ता: धन्यवाद, डॉ. शरण, आपने POSH कानून और इसके महत्व पर जो प्रकाश डाला, वह न केवल हमारी जानकारी बढ़ाने वाला है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रेरित करेगा।

'ऐतिहासिक कानूनों से तेज हुई विकास की गति', ओम बिरला बोले- विकास की चुनौतियां दूर करना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि समावेशी विकास के मार्ग में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का समाधान करना जनप्रतिनिधियों व विधायी निकायों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कार्यपालिका की जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करके शासन को अधिक जिम्मेदार व कुशल बनाती हैं।

नई दिल्ली। संसद भवन परिसर में आयोजित 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधानमंडलों की कार्यकुशलता और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया। साथ ही कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाएं कार्यपालिका की जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करके शासन को अधिक जिम्मेदार व कुशल बनाती हैं।

उन्होंने कहा कि समावेशी विकास के मार्ग में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का समाधान करना जनप्रतिनिधियों व विधायी निकायों की जिम्मेदारी है। 'सतत एवं समावेशी विकास में विधायी निकायों की भूमिका' विषय पर आयोजित अधिवेशन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का संविधान समावेशी शासन की भावना का सबसे सशक्त उदाहरण है।

'ऐतिहासिक कानूनों से तेज हुई विकास की गति'

उन्होंने कहा कि भारत की संसद द्वारा पारित ऐतिहासिक कानूनों से भारत में विकास की गति तेज हुई है और इससे भारत की प्रगति और अधिक समावेशी हुई है, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। विधायी संस्थाओं के सहयोग और समर्थन के बिना आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं होगा।

उन्होंने पीठासीन अधिकारियों और विधायकों से आग्रह किया कि वे इस बात पर चिंतन करें कि पिछले सात दशकों की यात्रा में देश के विधायी निकाय के रूप में वे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में कहां तक सफल रहे हैं। इस आत्ममंथन के बिना समावेशी विकास का सपना साकार नहीं हो सकता। इस अवसर पर राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश और राज्य विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारी भी उपस्थित थे।

ढेंकनाल जिला चिकित्सा केंद्र देखने में बहुत सुंदर है, मरीज आने पर खाली रेफर कर रहे हैं

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : ढेंकनाल जिला मेडिकल सेंटर की हालत का जिक्र न किया जाए तो बेहतर है, कि मरीज कुछ भी लेकर आए, उसे कटक रेफर किया जा रहा है, यह जिला मेडिकल सेंटर नहीं बल्कि रेफरल मेडिकल सेंटर है। यह मेडिकल सेंटर दिखने में मेडिकल कॉलेज जैसा लगता है, लेकिन यहां कोई डॉक्टर नहीं है। कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है। यदि आप मरीज को रखने का निर्णय लेते हैं लेकिन इस कागज पर हस्ताक्षर करते हैं तो मरीज के साथ जो होगा उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। माना है कि यहा कि प्रसूति वार्ड सही है, इसी का आलाबा ओर कुछ नहीं। इस ढेंकनाल मेडिकल सेंटर में सभी विभागों के प्रोफेसरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ईको, अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की सामान्य मांग है। बीआरपी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद नाइक, भारत गोरक्षा महासंघ के संयोजक मनोरचन साशमल और राष्ट्रीय बिकास सेना के अध्यक्ष बलाराजू अचारी ने मध्यम मांग की है।

हैदराबाद : गाड़ीमैसम्मा में हैदराबाद तेलंगाना की पवन भुमि पर राजस्थान रायरा कलां के चामुण्डा माता जी भोपाजी चन्द्रराम का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित। में महेन्द्र यादव, भंवरलाल, केसाराम, कालुराम, ताराराम, जगदीश, समाज बन्धु उपस्थित रहे।

देश में होनी चाहिए यौन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया ये सुझाव?

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अश्लील वीडियो के अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को समग्र रूप से यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया। इस कार्यक्रम में बच्चों की अश्लील वीडियो के कानूनी और नैतिक परिणामों को भी शामिल किया जाएगा। इससे अपराधियों को रोकने में मदद मिलेगी। यौन शिक्षा को लेकर फैले भ्रमों को दूर कर युवाओं को सहमति की स्पष्टता समझाई जानी चाहिए।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अश्लील वीडियो के अपराध पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार को समग्र रूप से यौन शिक्षा कार्यक्रम लागू करने का सुझाव दिया है। इस कार्यक्रम में अश्लील वीडियो के कानूनी और नैतिक परिणामों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे अपराधियों को रोकने में मदद मिल सकती है। इस कार्यक्रम में यौन शिक्षा को लेकर फैले भ्रमों को दूर कर युवाओं को सहमति और उत्पीड़न की स्पष्टता समझाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें अश्लील वीडियो देखने और उसकी सामग्री रखने को पोक्सो और आइटी कानून में अपराध बताने वाले फैसले में कही।

दिल्ली में अक्टूबर में होगी E-Vehicle परेड, राजघाट पर जुटेंगे 500 से अधिक वाहन

दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग अगले महीने राजघाट पर ई-वाहन परेड का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद और उपयोग बढ़ाना है। इस आयोजन में 500 से अधिक ईवी भाग लेंगे। परेड में भाग लेने वाले इच्छुक ई वाहन मालिकों के लिए पंजीकरण लिंक की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। निविदा 30 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी।

नई दिल्ली। पर्यावरण विभाग अक्टूबर की शुरुआत में राजघाट पर 'ई-वाहन परेड' का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद और उपयोग बढ़ाना है।

अधिकारियों का अनुमान है कि इस आयोजन में 500 से अधिक ईवी भाग लेंगे। परेड में भाग लेने वाले इच्छुक ई वाहन मालिकों के लिए पंजीकरण लिंक की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

टेंडर देने के पांच दिनों के भीतर परेड आयोजित

पर्यावरण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोजन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, जिस पर करीब 5.76 लाख रुपये खर्च होने की उम्मीद है। निविदा 30 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी और टेंडर दिए जाने के पांच दिनों के भीतर परेड आयोजित की जाएगी।

ईवी के उपयोग को बढ़ावा देना उद्देश्य

एक अधिकारी ने कहा, ₹प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली में ईवी के उपयोग को बढ़ावा देना और उनके लाभों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। हम अधिक से अधिक ईवी मालिकों को परेड में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वाहनों में बदलाव से राजधानी में वाहन प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जिन्होंने नई कैबिनेट के गठन के बाद सोमवार को ही अपना पदभार ग्रहण किया, ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले महीनों में आप सरकार का ध्यान वायु प्रदूषण से निपटने पर होगा।

सभी डरे हैं और सभी सहमें हैं।

अब तो सभी डरे हैं और सभी सहमें हैं।
खूब कड़वे अनुभव नेताओं को हुए हैं।
कौन हैं प्यारा और कौन सबसे है दुलारा,
अब किस-किसको जनता लाएगी दुबारा।
अपनी कांगेस पार्टी से हैं शिकवा-गिला,
शैलजा और सुरजेवाला को न्योता मिला।
सुना है भाजपा में भी छाई है निराशा,
इसी कारण कांग्रेस में आई है आशा।
फ़रि भी सभी डरे हैं और सभी सहमें हैं।
लोकसभा चुनाव ने भाजपा को डराया,
छतीसगढ़ ने कांग्रेस को भी सहमाया!
आप को भी शराब ने खूब है लजाया.
कार्यकर्त्ता भी खूब कला दिखा रहे है,
उम्मीदवार को भीतरघात से डरा रहें हैं।
अभी-भी सभी डरे हैं और सभी सहमें हैं।
खूब कड़वे अनुभव नेताओं को आ रहें हैं।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)
98260-25986

आयुष्मान भारत: पैसा नहीं मिला तो अस्पतालों ने इलाज बंद करने की दी चेतावनी

इलाज का पैसा नहीं मिलने पर अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत के तहत इलाज बंद करने की चेतावनी के बाद पंजाब सरकार इसके सुचारू संचालन जारी रखने की कोशिश में जुट गई है। इस सिलसिले में पंजाब सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। अभी तक योजना से बाहर रहे ओडिशा भी आयुष्मान भारत से जुड़ने की कोशिश में जुट गया है।

नई दिल्ली। इलाज का पैसा नहीं मिलने पर अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत के तहत इलाज बंद करने की चेतावनी के बाद पंजाब सरकार इसके सुचारू संचालन जारी रखने की कोशिश में जुट गई है। इस सिलसिले में पंजाब सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है, जिनमें योजना के तहत केंद्रीय सहायता की राशि जारी करने के लिए नियमों के जरूरी अनुपालन पर विस्तार से चर्चा हुई है।

इसी तरह से अभी तक योजना से बाहर रहे ओडिशा भी आयुष्मान भारत से जुड़ने की कोशिश में जुट गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले खर्च की 60 फीसद राशि केंद्र सरकार और 40 फीसद राज्य सरकार को देना होता है।

पंजाब सरकार ने नहीं दी आयुष्मान भारत योजना की रिपोर्ट

पर्वतीय राज्यों के लिए यह राशि 90 फीसद और 10 फीसद है। अस्पतालों को इलाज की खर्च का भुगतान राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। वहीं नियम के मुताबिक केंद्रीय सहायता की राशि हासिल करने के लिए राज्य सरकार को पूरे खर्च का आडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। पंजाब सरकार ने पिछले कई सालों से आयुष्मान भारत योजना की आडिट रिपोर्ट नहीं दी थी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले दिनों पंजाब ने 2020-21 की आडिट रिपोर्ट दी है और आगे की आडिट रिपोर्ट जल्द देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि आडिट रिपोर्ट मिलते ही केंद्रीय सहायता की राशि जारी कर दी जाएगी।

वहीं नवीन पटनायक सरकार के दौरान आयुष्मान भारत योजना से बाहर रहा ओडिशा भाजपा सरकार बनते ही इसमें शामिल होने की कवायद में जुट गया है। इसके लिए ओडिशा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ओडिशा में लोगों को मुफ्त इलाज के लिए अपनी योजना पहले से चल रही है। उसी योजना को आयुष्मान भारत से जोड़ा जाना है।

इस योजना से बाहर जाएगा पश्चिमबंगाल

दोनों पोर्टल के एकीकृत करने के लिए तकनीकी समाधान निकालने पर काम शुरू हो गया है। आयुष्मान भारत के तहत आने वाले परिवारों के पांच लाख रुपये के तहत इलाज का खर्च योजना के तहत वहन किया जाएगा। ओडिशा के आयुष्मान भारत में शामिल होने के बाद सिर्फ दिल्ली और पश्चिम बंगाल इस योजना से बाहर रह जाएंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023